Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 11
अंक : 67
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.0
रविवार, 15 मार्च, 2026

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 त्र्यंबक-नाशिक कुंभ मेला विश्व के लिए आकर्षण ... 4 उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच ... 7 विश्वकप ट्रॉफी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर...

संक्षिप्त न्यूज

विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, 5 भारतीयों की मौत, एक अब भी लापता

नई दिल्ली। अतिरिक्त सचिव (खाड़ी क्षेत्र) असीम महाजन ने शनिवार को बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में पांच भारतीय शहीद हो गए हैं, जबकि एक घायल हो गया है। उन्होंने कहा कि मिशन चौबीसों घंटे खुले हैं और सभी प्रकार की सहायता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। महाजन ने ये बातें राष्ट्रीय राजधानी में पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि पिछली घटना में पांच भारतीय शहीद हो गए हैं और एक लापता है। ओमान, इराक और यूएई में स्थित हमारे मिशन लापता भारतीय नागरिक के संबंध में संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मृतक के पार्थिव शरीर को शीघ्र स्वदेश वापस लाने के लिए प्रयासरत हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र में नाविकों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है और विदेश मंत्रालय बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) ने कहा कि बहरीन और कुवैत जैसे स्थानों के लिए, जहां से सीधी उड़ानें संचालित नहीं हो रही हैं, भारतीय नागरिकों को सऊदी अरब के रास्ते भारत आने के लिए वीजा विस्तार और ट्रांजिट वीजा में सहायता प्रदान की जा रही है।

उन्होंने ओमान के सोहार शहर में हुए हमले के बारे में जानकारी दी, जिसमें दो भारतीयों की मृत्यु हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। उन्होंने बताया कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। हमारा मिशन घटनास्थल पर मौजूद है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। संबंधित ओमानी अधिकारियों, स्थानीय कंपनियों, अस्पतालों और प्रभावित भारतीयों के परिवारों के साथ निरंतर संपर्क में है।

बंगाल में गरजे पीएम मोदी

बोले- टीएमसी ने आदिवासी राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में एक विशाल रैली के दौरान सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकी। भाजपा के परिवर्तन यात्रा अभियान के समापन पर समर्थकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने बंगाल की हालिया यात्रा के दौरान राष्ट्रपति का अपमान किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ ही दिन पहले, हमारी देश की राष्ट्रपति, आदिवासी समुदाय की सम्मानित पुत्री, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बंगाल आई थीं। उन्हें संथाल आदिवासी परंपरा के पवित्र उत्सव में भाग लेना था, लेकिन इस अहंकारी और निर्दयी सरकार ने न केवल उस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, बल्कि उसे पूरी तरह अराजकता में बदल दिया। उन्होंने आगे कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी नेता को दिए गए सम्मान को स्वीकार नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि क्योंकि आदिवासी समुदाय की पुत्री इतने उच्च पद पर हैं, इसलिए टीएमसी के लोग उनके सम्मान को स्वीकार नहीं कर सके। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में राजनीतिक परिवर्तन अपरिहार्य है और उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य में महा जंगलराज लाने का आरोप लगाया।

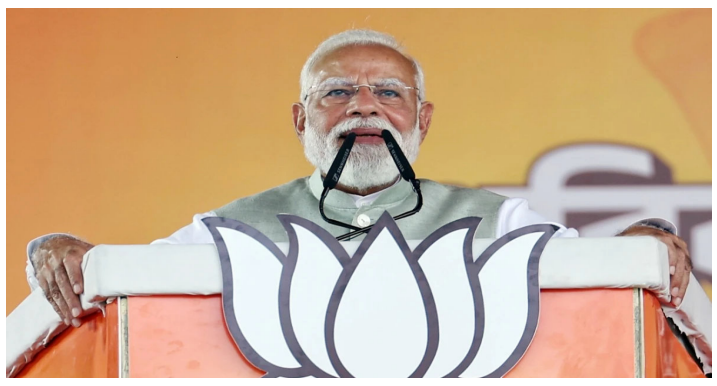

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह निरंकुश सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, परिवर्तन की इस आंधी को रोक नहीं पाएगी। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में सत्ताधारी पार्टी के पतन की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं को रोककर राज्य में विकास में बाधा डाल रही है। उन्होंने कहा, 'टीएमसी न तो खुद काम करती है और न ही दूसरों को काम करने देती है। बंगाल में कई केंद्रीय योजनाएं ठप पड़ी हैं।' उन्होंने राज्य सरकार पर लोगों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं को रोकने का आरोप लगाया।

राज्य में युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई युवा अवसरों की तलाश में बंगाल छोड़ने को मजबूर हैं। उन्होंने रैली के दौरान कहा कि बंगाल के युवा पलायन के अभिशाप से पीड़ित हैं। उन्हें न तो डिग्री मिल रही है और न ही नौकरियां। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में राजनीतिक परिवर्तन होते ही कानून का कड़ा शासन फिर से लागू होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में फिर से कानून का शासन होगा। अत्याचारों के आरोपी टीएमसी नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा।

एलपीजी की कमी पर देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले- देश को गुमराह करना बंद करें

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश में एलपीजी की कमी की खबरों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर लोगों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और लोगों को गैस के लिए लंबी कतारों में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि चाहे महाराष्ट्र हो या देश का कोई अन्य हिस्सा, कहीं भी एलपीजी की कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार, संबंधित विभागों और तेल कंपनियों ने भी स्पष्ट किया है कि देश में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। इसके बावजूद कांग्रेस और उसके कुछ नेता जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से घबराहट पैदा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों को कतारों में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है और कांग्रेस को देश को भ्रमित करना बंद करना चाहिए।

उधर, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। इसी बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि भारत में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और देश भर की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। खुदरा दुकानों पर ईंधन की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर आयोजित अंतर-मंत्रालयी बैठक में मंत्रालय की संयुक्त सचिव (विपणन एवं तेल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और फिलहाल आयात की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल एलपीजी की किसी कमी की सूचना नहीं है, हालांकि मौजूदा वैश्विक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पश्चिम बंगाल-असम चुनाव में 'लाठी' के साथ तैनात होगी 'बीएसएफ', असमंजस में हैं 'सीमा सुरक्षा बल' के जवान

कोलकाता। पश्चिम बंगाल और असम में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की लगभग पांच सौ कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। सीमा सुरक्षा बल 'बीएसएफ' के जवानों से कहा गया है कि वे चुनावी ड्यूटी के दौरान अपने हाथों में 'लाठी' रखें। सूत्रों के मुताबिक, बीएसएफ डीजी ने यह हिदायत दी है। नॉर्थ बंगाल के आईजी सहित कई अफसरों को यह आदेश ठीक नहीं लग रहा। इसके अलावा बीएसएफ जवान भी 'लाठी' वाले आदेश से असमंजस में हैं। वजह, पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव में कई स्थानों पर हिंसा हुई थी। असम में भी कई ऐसे इलाके हैं, जो विधानसभा चुनाव के लिहाज से अति संवेदनशील माने जाते हैं।

क्यों गले नहीं उतर रहा ये आदेश

बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार ने पिछले दिनों गुवाहाटी, साउथ बंगाल और नॉर्थ बंगाल के आईजी के साथ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने को लेकर बैठक की थी। उस बैठक में डीजी ने अफसरों को अवगत कराया कि इस बार चुनावी ड्यूटी के दौरान बीएसएफ जवान अपने पास 'लाठी' रखेंगे। हालांकि बैठक में मौजूद बीएसएफ अफसरों को डीजी के आदेश पर हैरानी हुई।

नीतिश कुमार के बाद बिहार की कमान किसके हाथ? जेडीयू सांसद बोले- एनडीए आलाकमान करेगा फैसला

पटना। जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बिहार की सभी पांच राज्यसभा सीटों पर जीत का पूरा भरोसा है और उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री का फैसला गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। मीडिया से बात करते हुए झा ने कहा कि राज्य में आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों के तहत जेडीयू विधायक दल की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हो रही है, कल यह बैठक मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास पर होगी।

राज्यसभा चुनावों में एनडीए की संभावनाओं पर विश्वास जताते हुए झा ने कहा कि गठबंधन को क्लीन स्वीप

की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम सभी पांच राज्यसभा सीटें जीतेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के सवाल पर झा ने कहा कि इस मामले का फैसला एनडीए के शीर्ष नेता मिलकर करेंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए के शीर्ष नेता ही तय करेंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये टिप्पणियां बिहार में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच आई हैं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जिससे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनके लंबे कार्यकाल के अंत का संकेत मिला। कुमार ने पहले जोर देकर कहा था कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार लगातार प्रगति कर रहा है।

इस सप्ताह की शुरुआत में मधेपुरा में समृद्धि यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जिले में विकास हो रहा है। बिहार को केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार हर तरह से प्रगति करेगा और देश के प्रगतिशील राज्यों में शुमार होगा। इसी बीच, कुमार के बेटे निशांत कुमार ने 8 मार्च को औपचारिक रूप से जेडीयू में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए निशांत कुमार ने अपने पिता के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि वे उन पर रखे गए भरोसे को कायम रखने के लिए काम करेंगे।

ईंधन की जमाखोरी पर मंत्रालय की सख्त चेतावनी

कहा- देश में तेल का पर्याप्त भंडार, घबराकर खरीदारी न करें

नई दिल्ली। अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नागरिकों से ईंधन की जमाखोरी न करने की अपील की है। मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को घबराकर खरीदारी करने की जरूरत नहीं है। साथ ही सरकार ने असुरक्षित तरीके से ईंधन बेचने और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में तमिलनाडु के एक पेट्रोल पंप को नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण ईंधन आपूर्ति को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। इसके बीच मंत्रालय ने शनिवार को एक परामर्श जारी कर नागरिकों को आश्वस्त किया कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने लोगों से यह भी अपील की है कि वे पेट्रोल या डीजल को खुले या अनुचित डिब्बों में न रखें, क्योंकि इससे गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है।

मंत्रालय ने बताया कि तमिलनाडु में एक पेट्रोल पंप पर खुले कंटेनर में पेट्रोल बेचने का मामला सामने आया था, जो सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। इस मामले में संबंधित पेट्रोल पंप को निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इसके अलावा मंत्रालय ने देशभर के सभी ईंधन विक्रेताओं और डीलरों को निर्देश दिया है कि पेट्रोल और डीजल की बिक्री के दौरान सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (विपणन एवं तेल शोधन) सुजाता शर्मा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि लोग घबराकर गैस या ईंधन की बुकिंग न करें और केवल आवश्यकता होने पर ही बुकिंग करें। उन्होंने बताया कि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के संबंध में भी चर्चा के बाद एक निश्चित मात्रा आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकारों से समन्वय किया गया है और उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए व्यावसायिक सिलेंडर राज्यों को उपलब्ध कराए गए हैं। लगभग 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन सिलेंडरों का वितरण शुरू हो चुका है और वे उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए देशभर में लगातार छापेमारी और अचानक निरीक्षण किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान में संयुक्त टीमों ने छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 1400 स्थानों पर निरीक्षण किए गए, जिनमें करीब 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगभग 19 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शुरू किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा और कर्नाटक में भी कार्रवाई की गई है।

सोनम वांगचुक की रिहाई पर केजरीवाल का हमला, बोले- मोदी सरकार की तानाशाही हुई बेनकाब

नई दिल्ली। सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हुई हिरासत रद्द होने के बाद आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए इसे 'स्पष्ट तानाशाही' करार दिया और कहा कि इस फैसले से केंद्र सरकार एक बार फिर बेनकाब हो गई है।

शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए एक पोस्ट में केजरीवाल ने कहा कि एक वैज्ञानिक और जलवायु कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया, उन्हें बिना किसी ठोस सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि जेल में बिताए गए महीने न केवल सोनम वांगचुक के लिए व्यक्तिगत नुकसान थे, बल्कि देश के लिए भी हानि साबित हुए। केजरीवाल ने कहा कि इस प्रकार की स्पष्ट तानाशाही का पर्दाफाश होना चाहिए और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

इसी बीच, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केजरीवाल को 22 अन्य लोगों के साथ दिल्ली की एक विशेष अदालत ने रिहा कर दिया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी सोनम

वांगचुक की रिहाई के फैसले का स्वागत किया और बिना मुकदमे के लंबी हिरासत पर सवाल उठाए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया कि बिना मुकदमे के अधिकतम अनुमेय हिरासत अवधि के लिए स्पष्ट और सख्त मानदंड तय किए जाएं। उन्होंने कहा कि बिना मुकदमे के अनिश्चितकालीन हिरासत औपनिवेशिक काल से चली आ रही एक अलोकतांत्रिक प्रथा है और एक परिपक्व लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। थरूर ने कहा कि 169 दिनों की हिरासत काफी लंबी अवधि है।

उधर, गृह मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत उपलब्ध शक्तियों का उपयोग करते हुए सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय के अनुसार यह कदम लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल मजबूत करने तथा सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार लद्दाख के विभिन्न हितधारकों और सामुदायिक नेताओं के साथ लगातार बातचीत कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं और चिंताओं का समाधान किया जा सके।

ओडिशा राज्यसभा चुनावः पटनायक का भाजपा पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप, भाजपा ने नकारा

ओडिशा। बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने शनिवार, 14 मार्च को भाजपा पर आगामी राज्यसभा चुनावों में 'विधायकों की खरीद-फरोख्त' का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक अपराध बताया। यह टिप्पणी राज्य में क्रॉस-वोटिंग की आशंका के बीच आई है, जहां चार सीटों के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में हैं।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक जय नारायण मिश्रा ने पटनायक के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने ऐसी किसी खरीद-फरोख्त से इनकार किया। भाजपा के आधिकारिक उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त है। बीजद के उम्मीदवार संतृप्त मिश्रा और डॉ. दत्तेश्वर होता हैं, जिन्हें कांग्रेस और सीपीआईएम का समर्थन है। चौथी सीट जीतने के लिए किसी भी पार्टी के पास पर्याप्त संख्या नहीं है, जिससे क्रॉस-वोटिंग की संभावना बढ़ गई है।

पटनायक का आरोप

विधानसभा परिसर में मॉक-पोल सत्र के बाद नवीन पटनायक ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता और उनके तीनों राज्यसभा उम्मीदवार विधायकों की खरीद-फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। पटनायक ने इसे लोकतांत्रिक चुनाव जीतने का अपराध बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी प्रथा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

भाजपा का पलटवार

भाजपा विधायक जय नारायण मिश्रा ने पटनायक के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजद प्रमुख ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। मिश्रा ने कहा कि जो व्यक्ति पीलिया से पीड़ित होता है, उसे सब कुछ पीला ही दिखता है।

कौशल, रोजगार और श्रम कल्याण पर खर्च होंगे रू 2,902 करोड़, सरकार का बड़ा ऐलान

अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को मजबूत करने और श्रमिकों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, श्रम मंत्री कुंवरजी बावलिया ने शनिवार को घोषणा की कि 2026-27 के बजट में श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग के लिए 2,902 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है।

गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि राज्य विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बावलिया ने कहा कि यह बजट 'विकसित गुजरात 2047' के विजन को साकार करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गुजरात सरकार ने राज्य भर में कौशल विकास, रोजगार के अवसर और श्रमिक कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नई योजनाओं और बजट आवंटन की घोषणा की है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नमो गुजरात कौशल एवं रोजगार मिशन के तहत युवाओं

की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए 226 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पीएम सेतु योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से उन्नत किया जाएगा ताकि राज्य के कौशल प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार ने नमो कौशल्या लक्ष्मी योजना के लिए 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिसका उद्देश्य छात्राओं को आईटीआई में पाठ्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, छात्राओं को एक वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए 15,000 रुपये और दो वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए 24,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। राज्य सरकार ने कई श्रमिक कल्याणकारी पहलों का विस्तार भी किया है। श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 300 नए अन्नपूर्णा बूथ खोले जा सकेंगे, जहां श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। श्रमिक बसेरा योजना के लिए 150 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को किफायती आवास प्रदान करना है।

दर्जेदार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 'पल्स मेडिकल कॉन्फ्रेंस' महत्वपूर्ण

'पल्स' के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक आधुनिक और तकनीक से सुसज्जित होगी - चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री माधुरी मिसाल

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और तकनीक आधारित बनाए बिना राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक आधुनिक, तकनीक से सुसज्जित, शोध आधारित और सर्वसमावेशी बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इस सम्मेलन में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के विद्यार्थी, डीन, विशेषज्ञ, निजी शैक्षणिक संस्थान तथा आधुनिक चिकित्सा उपकरण बनाने वाली कंपनियां भाग लेंगी। इससे राज्य में मेडिकल टूरिज्म और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।

'पल्स मेडिकल कॉन्फ्रेंस' का आयोजन 27 और 28 मार्च 2026 को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, बीकेसी में किया गया है। इस सम्मेलन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा, शोध, औषधि निर्माण उद्योग, स्टार्टअप तथा वेलनेस पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों को एक मंच पर लाकर भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा तय करने का प्रयास किया जाएगा। यह सम्मेलन केवल चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ठोस निर्णय, निवेश समझौते, नीतिगत बदलाव और जनता के लिए प्रत्यक्ष लाभ देने वाला मंच बनेगा।

राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी है और देश-विदेश के विशेषज्ञ, शोधकर्ता, उद्योगपति और नीति निर्माता इस सम्मेलन में भाग लेंगे। उनके सहभाग से नई तकनीक, आधुनिक उपचार पद्धतियां और बड़े पैमाने पर निवेश राज्य में आने में मदद मिलेगी। इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं, डॉक्टरों को नई संभावनाएं और विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शिक्षा व शोध का अनुभव

प्राप्त होगा।

विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी प्रत्यक्ष अनुभव से मिले, यही इसका उद्देश्य है। आयुष क्षेत्र में आयुर्वेद और एलोपैथी के समन्वय से एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही फार्मेसी क्षेत्र के नए शोध, डॉक्टरों के शोध पत्र और नवाचार भी सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाएंगे।

इस पहल को चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ का विशेष मार्गदर्शन प्राप्त है। सम्मेलन की पूर्व तैयारी का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों किया गया। सम्मेलन में लगभग 2,900 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनके लिए क्यूआर कोड आधारित प्रवेश, अलग-अलग सत्र हॉल, हेल्पडेस्क, स्वयंसेवक और लाइव स्क्रीनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा सुरक्षा, आपातकालीन चिकित्सा सेवा, परिवहन और आवास व्यवस्था के लिए अलग समन्वय कक्ष भी कार्यरत रहेगा।

सम्मेलन के प्रमुख विषयों में डिजिटल हेल्थ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिकित्सा शिक्षा में सुधार और कौशल विकास, शोध और नवाचार, मेडिकल और वेलनेस पर्यटन, निवेश तथा ग्रामीण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना शामिल है। नागरिकों को अधिक गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इन विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी।

सम्मेलन में 'डिजी डोम' और 'टेक टॉक' जैसी विशेष अवधारणाएं भी शामिल की गई हैं। 360 डिग्री डोम में रोबोटिक सर्जरी, वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से मेडिकल प्रशिक्षण और डिजिटल अस्पताल प्रबंधन जैसी तकनीकों का लाइव और प्रभावी प्रदर्शन किया जाएगा। टेक टॉक सत्रों में देश-विदेश के विशेषज्ञ, शोधकर्ता और उद्योग जगत के नेता अपने अनुभव और नए विचार साझा करेंगे। इससे युवा डॉक्टरों, विद्यार्थियों और स्टार्टअप उद्यमियों को प्रेरणा और दिशा मिलेगी।

इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार की जाएगी। शोध और तकनीक के क्षेत्र में नई साझेदारी, चिकित्सा शिक्षा में सुधार, निवेश और स्टार्टअप परियोजनाओं की घोषणा की उम्मीद है। रोबोटिक सर्जरी, वर्चुअल रियलिटी आधारित शिक्षा और तकनीक आधारित उपचार प्रणाली भविष्य की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सशक्त बनाएगी।

महाराष्ट्र वेलनेस पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं, समुद्र तट, हिल स्टेशन, जंगल क्षेत्र तथा योग, आयुर्वेद, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों के कारण राज्य में वेलनेस पर्यटन की बड़ी संभावनाएं हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और प्राकृतिक उपचार पद्धतियों को जोड़कर राज्य को वैश्विक वेलनेस गंतव्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। वेलनेस पर्यटन से ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। स्थानीय युवाओं को योग प्रशिक्षक, थेरेपिस्ट या गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। महिला स्वयं सहायता समूहों को हर्बल उत्पाद, स्थानीय भोजन और होमस्टे जैसी सुविधाएं चलाने का अवसर मिलेगा। औषधीय पौधों की खेती और हर्बल फार्मिंग से किसानों की आय भी बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय मरीजों को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। मेडिकल वीजा प्रक्रिया को सरल बनाना, प्रमुख शहरों में अंतरराष्ट्रीय मरीज सहायता केंद्र स्थापित करना, बहुभाषी मार्गदर्शन उपलब्ध कराना और हवाई अड्डे से अस्पताल तक समन्वय व्यवस्था विकसित करना जैसे कदम उठाए जाएंगे।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नवी मुंबई महानगरपालिका में विशेष कार्यशालाओं के माध्यम से स्वच्छता पर क्षमता निर्माण

दिव्यांश

मुंबई। स्वच्छ भारत मिशन (सिविल) 2.0 के अंतर्गत कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण योजना तैयार की गई है। इसके तहत सरकारी संस्थानों के सभी स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता के विषय में प्रशिक्षण देकर उनकी क्षमता विकसित की जा रही है। इसी के अंतर्गत देशभर में प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 23 स्वच्छता ज्ञान साझेदार नियुक्त किए गए हैं। इनके माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

इसी क्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत विश्व महिला दिवस सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों के हिस्से के रूप में स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (सिविल) के निर्देशानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। ज्ञान केंद्र में आयोजित इस महिला स्वच्छता कर्मियों के क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यशाला में 250 से अधिक महिला स्वच्छता कर्मियों के साथ संबंधित अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी शामिल हुए। यह कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

स्वच्छता पर आयोजित इस क्षमता निर्माण कार्यशाला में स्वच्छता ज्ञान साझेदार संस्था हिमालयन इंस्टिट्यूट फॉर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट द्वारा ऑर्नेट टेक्नोलॉजीज के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया। ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तित्व और बृहन्मुंबई महानगरपालिका के ठोस कचरा प्रबंधन विभाग के सेवानिवृत्त विशेष कर्तव्य अधिकारी श्री आनंद जगताप तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के प्रशिक्षक श्री तिक्सला गायकवाड़ ने प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया।

महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे और अतिरिक्त आयुक्त श्री सुनील पवार के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में उप आयुक्त डॉ. अजय गाडे और मुख्य स्वच्छता अधिकारी श्री नरेश अंधेर उपस्थित रहे और उन्होंने इस कार्यशाला के महत्व को रेखांकित किया।

'नोटबंदी जैसी कतारें', एलपीजी संकट पर संजय राउत का सवाल– प्रधानमंत्री मोदी कहां हैं?

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

देश में एलपीजी की कमी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने शनिवार को केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार समस्या का समाधान करने के बजाय चुनाव प्रचार में व्यस्त है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।

संजय राउत ने कहा कि एलपीजी सिलेंडरों की कमी के कारण लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, जो नोटबंदी के समय लगी कतारों जैसी स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने दावा किया कि गैस की कमी के कारण लगभग 40 प्रतिशत होटल उद्योग प्रभावित हो गया है और कई जगहों पर कामकाज ठप हो गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही यह कह रही हैं कि सब कुछ सामान्य है, जबकि जमीन पर स्थिति अलग दिखाई दे रही है। राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता इस समय दक्षिण भारत में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, जबकि जनता गैस सिलेंडर के लिए परेशान हो रही है।

राउत ने यह भी कहा कि इस स्थिति के लिए सरकार की अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विफलता जिम्मेदार है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ईरान जैसे देशों के साथ किस आधार पर बातचीत करेगी और कहा कि भारत को तटस्थ रुख अपनाते हुए ईरान को नैतिक समर्थन देना चाहिए।

भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में 'नरेंद्रभाई गायब, सिलेंडर गायब' जैसे नारे सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक कौन बुलाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं।

इस बीच, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। हालांकि एलपीजी की स्थिति को लेकर सरकार सतर्क है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव (विपणन एवं तेल शोधन) सुजाता शर्मा ने बताया कि 5 मार्च की तुलना में घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ताकि आपूर्ति को मजबूत किया जा सके और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

भारतीय रेलवे में रेल समयबद्धता के मामले में मध्य रेल का भुसावल मंडल प्रथम स्थान पर मार्च माह में अब तक 4 दिनों तक 100% समयबद्धता हासिल की गई

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

दिनांक 13.03.2026 को भारतीय रेलवे के 69 मंडलों में मध्य रेल के भुसावल मंडल ने रेल परिचालन में समयबद्धता के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दिनांक 13.03.2026 को निर्धारित प्रादेशिक दूरी 54067.25 किमी थी और निर्धारित समय 54074 मिनट था। एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस) में दर्ज 173 ट्रेनों में से प्रत्येक ट्रेन समय पर चली, जिसके परिणामस्वरूप 100इ समयबद्धता का रिकॉर्ड बना। यह दूसरे स्थान पर रहे मंडल (जोधपुर) से दोगुने से भी अधिक है और हुब्बलि , राजकोट और भावनगर मंडलों (154 ट्रेनें) के संयुक्त कुल से भी अधिक है। यह भारतीय रेलवे में किसी भी मंडल द्वारा संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की 11वीं सबसे अधिक संख्या को भी दर्शाता है।

भुसावल मंडल के इतिहास में यह पहली

बार है कि मंडल स्तर पर 100इ समयबद्धता हासिल की गई है, जिसने दिनांक 11.03.2026 को बनाए गए पिछले रिकॉर्ड 98.32इ को पार कर लिया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

मंडल और जोनल दोनों स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए, भुसावल मंडल ने मध्य रेल को 17 जोनल रेलवे में 5वें स्थान पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह इस महीने (3, 5, 11 और 13 मार्च) चौथी बार 100इ जोनल समयबद्धता का स्कोर है।

प्रतिदिन औसतन 170 से अधिक ट्रेनों के साथ मेल एक्सप्रेस यातायात की भारी मात्रा ट्रेन संचालन का प्रबंधन करना बेहद चुनौतीपूर्ण बना देती है। ट्रेनों की अधिक संख्या और लंबी दूरी के कारण नियंत्रकों पर ट्रेनों पर शुरू से अंत तक नजर रखने का बोझ बढ़ जाता है।

यह उपलब्धि ऑपरेटिंग शाखा के सभी कर्मचारियों की लगातार 'मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग' का नतीजा है, जिसका उद्देश्य मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को प्राथमिकता देना और समय की पाबंदी में किसी भी तरह की चूक के प्रति 'ज़ीरो-टॉलरेंस पॉलिसी' का पालन करना है।

मध्य रेल ने आज तक 92इ की समग्र समयबद्धता भी हासिल की है।

ये उपलब्धियां सेवाओं की विश्वसनीयता और समयबद्धता में सुधार करते हुए उच्च यात्री भार को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के उद्देश्य से मध्य रेल के निरंतर प्रयासों और रणनीतिक योजना को रेखांकित करती हैं।

परिचालन उत्कृष्टता पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए, मध्य रेल जनता को अधिक तत्परता और बेहतर सेवा गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

'बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला...', सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

गृह मंत्रालय द्वारा पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हुई हिरासत रद्द किए जाने के बाद एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार की नीति पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि एक बेकसूर व्यक्ति को छह महीने तक जेल में रखने की जिम्मेदारी कौन लेगा।

वारिस पठान ने कहा कि यह खुशी की बात है कि पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया है और उनके खिलाफ लगाया गया कानून हटा लिया गया है। लेकिन उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वांगचुक निर्दोष थे, तो उन्होंने जो छह

महीने जेल में बिताए उसकी भरपाई कौन करेगा। उन्होंने कहा कि वांगचुक एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, जिनके जीवन से प्रेरित होकर प्रसिद्ध फिल्म 'थ्री इडियट्स' भी बनाई गई थी।

पठान ने आगे कहा कि सोनम वांगचुक जलवायु और पर्यावरण के मुद्दों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और वे संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद उन पर सख्त धाराएँ लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया और छह महीने बाद रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रिहाई अच्छी बात है, लेकिन सरकार की नीति पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

उन्होंने यह भी मांग की कि लद्दाख में धरना-प्रदर्शन के दौरान जिन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी सरकार रिहा करे।

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार (14 मार्च) को एक बयान जारी कर कहा कि विचार-विमर्श के बाद सरकार ने सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार लद्दाख में शांति और सुरक्षा बनाए रखने तथा क्षेत्र की स्थिरता के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि लेह के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया था। दरअसल 24 सितंबर 2025 को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह कार्रवाई की गई थी।

'मैं उसे मारकर आया हूं', शख्स ने शक के चलते पत्नी की गला दबाकर की हत्या, थाने पहुंचकर किया सरेंडर

कल्याण। महाराष्ट्र के कल्याण से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां चरित्र पर शक के कारण एक पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी पति विशाल भुतकर ने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहा, 'मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है.' इस कबूलनामे ने पुलिस को भी कुछ देर के लिए हिला दिया.

नासिक के सरकारवाडा पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति अपने भाई को लेकर आया और उसने बताया कि 'मेरा भाई क्या बोलता है, सुनो.' इसके बाद पुलिस ने विशाल से पूछताछ की, जिसमें उसने कबूल किया कि उसने कल्याण के उम्बर्डे इलाके में जाकर अपनी पत्नी अर्चना भुतकर का गला दबाकर हत्या की. जानकारी की पुष्टि के लिए नासिक पुलिस ने तुरंत खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन से संपर्क किया. पुलिस दल ने घटनास्थल पर जाकर मृतका को मृत अवस्था में पाया.

पारिवारिक विवाद और चरित्र के शक ने दिया हत्या का कारण

प्रारंभिक जांच में पता चला कि विशाल और अर्चना के बीच पिछले कुछ महीनों से पारिवारिक विवाद चल रहा था. दोनों के दो बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा विशाल के पास और दूसरा बच्चा अर्चना की मां के पास रहता था. विशाल ने पत्नी के चरित्र पर शक करने के कारण गुस्से में उसे मारने की बात कबूल की. घटना के बाद नासिक पुलिस ने जानकारी देने के बाद खड़कपाड़ा पुलिस ने पंचनामा कर आगे की जांच शुरू कर दी.

पश्चिम रेलवे

विद्युत एवं सिविल कार्य

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (पावर) / मुंबई सेंट्रल, पश्चिम रेलवे द्वारा ई-टेंडर संख्या : EL-166-160-WA-84 (R), दिनांक 11.03.2026 (दो पैकेट प्रणाली) आमंत्रित किए जाते हैं। **कार्य एवं स्थान :** मुंबई मंडल (गैर-उपनगरीय खंड) के स्टेशनों के फुट ओवर ब्रिज पर 27 लिफ्ट लगाने का प्रावधान (विद्युत एवं सिविल कार्यों का संयुक्त टेंडर)। **कार्य की अनुमानित लागत :** 17,04,37,423.81 रुपये। **बयाना राशि:** 10,02,200 रुपये। **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :** 06.04.2026, दोपहर 15:00 बजे तक। **निविदा खोलने की तिथि एवं समय :** 06.04.2026, दोपहर 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट देखें :www.ireps.gov.in 1222

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

निगरानी एवं संचालन कार्य

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/पावर/बीसीटी, पश्चिम रेलवे, मुंबई सेंट्रल द्वारा ई-निविदा संख्या EL-Maint-166-138-WA-18, दिनांक 11-03-2026 (दो पैकेट प्रणाली) आमंत्रित की जाती है। **कार्य एवं स्थानः** मुंबई मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 01 वर्ष के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट की निगरानी एवं संचालन का कार्य। **कार्य की अनुमानित लागतः** 3,62,63,760/- **जमानत राशि (ईएमडी):** 3,31,300/- **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समयः** 10.04.2026, समय 15:00 बजे तक। **निविदा खोलने की तिथि व समयः** 10.04.2026, समय 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएँ। 1223

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

विद्युत एवं सिविल कार्य

वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (पावर) / मुंबई सेंट्रल, पश्चिम रेलवे द्वारा ई-टेंडर संख्या : EL-166-159-WA-83 (R), दिनांक 11.03.2026 (दो पैकेट प्रणाली) आमंत्रित किए जाते हैं। **कार्य एवं स्थान :** मुंबई मंडल (उपनगरीय खंड) में स्टेशनों के फुट ओवर ब्रिज पर 16 लिफ्ट लगाने का प्रावधान (विद्युत एवं सिविल कार्यों का संयुक्त टेंडर)। **कार्य की अनुमानित लागत :** 10,55,78,303.57 रुपये। बयाना राशि (इअ) : 6,77,900 रुपये। **निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :** 06.04.2026, दोपहर 15:00 बजे तक। **निविदा खोलने की तिथि एवं समय :** 06.04.2026, दोपहर 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट देखें : www.ireps.gov.in 1218

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक - मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे
मंडल रेल प्रबंधक, वाणिज्य विभाग, एनएफआर अनुभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400008।

कार्य - मुंबई मंडल में विभिन्न एनएफआर माध्यमों के माध्यम से विज्ञापन का प्रदर्शन।

नीलामी कैटलॉग संख्या	नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-ADVTH25-04	06-04-26 13:00:00

अ. क्र.	लॉट संख्या	स्थान / क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि एवं समय
1	**HyB-OnB-99674-25-1** (Hybrid NFR- On-board Hybrid)	मुंबई मंडल, पश्चिम रेलवे की नामित मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के आरक्षित कोचों में विज्ञापनों सहित लिनेन कवर बैग की खरीद एवं आपूर्ति के लिए 03 वर्ष की अवधि का अनुबंध।	1096	06-04-26 13:30:00

नीलामी कैटलॉग संख्या	नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-ADVTM25-59	06-04-26 14:00:00

अ. क्र.	लॉट संख्या	स्थान / क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि एवं समय
1	**MSS-BCT-CCG-PrKiosk-104-26-1** (Misc-Static-Services-Promotional Kiosk)	मुंबई मंडल के रेलवे स्टेशनों पर वर्चुअल ब्रांड प्रमोशनल कियोस्क (वीबीपीके) का विकास, संचालन और प्रबंधन।	1096	06-04-26 14:30:00
2	**MSS-BCT-VLP-MedStn-97-26-1** (Misc-Static-Services-Medical facilities at station)	विले पार्ले रेलवे स्टेशन पर आपातकालीन चिकित्सा कक्ष के माध्यम से चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने का कार्य, अवधि 05 वर्ष।	1826	06-04-26 14:40:00

नीलामी कैटलॉग संख्या	नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-ADVTM25-60	07-04-26 14:00:00

अ. क्र.	लॉट संख्या	स्थान / क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि एवं समय
1	**MSS-BCT-NSP-MedStn-46-24-1** (Misc-Static-Services-Medical facilities at station)	नालासोपारा रेलवे स्टेशन पर आपातकालीन चिकित्सा कक्ष के माध्यम से चौबीसों घंटे चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने का कार्य, अवधि 05 वर्ष।	1826	07-04-26 14:30:00

नीलामी कैटलॉग संख्या	नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट)
MMCT-ADVT-25-83	07-04-26 15:00:00

अ. क्र.	लॉट संख्या	स्थान / क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि एवं समय
1	**ADVT-BCT-BVI-OH-468-26-1** (Advertising - Out of Home)	बोरीवली सर्कुलेटिंग क्षेत्र में 20 ग्लोसाइन लगाकर कुल 592 वर्ग फुट क्षेत्रफल में थोक विज्ञापन अधिकार प्रदान करना, अवधि 05 वर्ष।	1826	07-04-26 15:30:00

संपर्क विवरणः लैंडलाइन नंबरः 02267644212 ईमेल आईडीः acmadvtgbct@gmail.com नोटः संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे आईआरईपीएस की वेबसाइट (www.ireps.gov.in) पर ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल पर जाएं। लॉट के अनुसार विस्तृत जानकारी वहां उल्लिखित कैटलॉग के अंतर्गत उपलब्ध है। 1224

Like us on: facebook.com/WesternRly • Follow us on: X.com/WesternRly

सौर इनगॉट और वेफर उत्पादन परिसर से नागपुर बनेगा देश का प्रमुख केंद्र – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वारी एनर्जी के 10 गीगावाट एकीकृत परियोजना का भूमिपूजन

नागपुर।सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एकीकृत इनगॉट और वेफर उत्पादन परिसर नागपुर में वारी एनर्जी के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है। भारत में सबसे बड़ी 10 गीगावाट क्षमता वाली यह परियोजना सौर क्षेत्र के लिए स्थिर घरेलू आपूर्ति प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इस परियोजना से नागपुर की पहचान सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख केंद्र के रूप में बनेगी, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किया।

अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र में वारी एनर्जीज लिमिटेड के माध्यम से भारत की सबसे बड़ी 10 गीगावाट क्षमता वाली एकीकृत इनगॉट और वेफर उत्पादन परियोजना का भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ। इस अवसर पर उन्होंने मार्गदर्शन किया। इस मौके पर वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री अधिवक्ता आशीष जयसवाल, गृह राज्य मंत्री डॉ. पंकज भोयर, वारी एनर्जी के अध्यक्ष हितेशभाई दोशी, सांसद श्यामकुमार बर्वे, विधायक समीर मेघे, पूर्व सांसद अजय संचेती, वारी एनर्जीज के वीरेंद्र दोशी, अंकित दोशी, करण दोशी, उद्योग विभाग के सचिव डॉ. पी. अन्बलगन, मुख्यमंत्री के मुख्य निवेश सलाहकार कौस्तुभ धवसे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उत्पादन में

आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही यह परियोजना 300 एकड़ क्षेत्र में लगभग 6,200 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित की जा रही है। इस परियोजना से लगभग 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि पूरे प्रकल्प में भविष्य में लगभग 30,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है और इसके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। एकीकृत इनगॉट और वेफर उत्पादन अब तक मुख्य रूप से चीन में होता था, लेकिन इस परियोजना के माध्यम से नागपुर में इसका उत्पादन शुरू होगा। चीन के बाद दुनिया के सबसे बड़े प्रकल्पों में शामिल होने के साथ ही यह परियोजना निर्यात क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहचान बनाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऐसे 7 प्रकल्पों को मंजूरी दी है, जिनमें से 4 महाराष्ट्र में स्थापित किए जा रहे हैं और उनमें से 3 का भूमिपूजन हो चुका है। महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दे रहा है। इसी कारण दावोस में राज्य में निवेश के लिए कई समझौते किए गए हैं।

मुख्यमंत्री सौर योजना के माध्यम से 16,000 मेगावाट क्षमता पूरी करने के लिए तेज गति से काम किया जा रहा है। अब तक लगभग 5,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो चुका है और सभी किसानों को सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि थर्मल पावर से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 300 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता होगी, जबकि सौर ऊर्जा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। सौर ऊर्जा उत्पादन से बिजली दरों में लगभग 9 प्रतिशत तक कमी आएगी और सौर ऊर्जा ने दुनिया भर में एक नई ऊर्जा क्रांति पैदा की है। कार्यक्रम की शुरुआत वारी एनर्जीज लिमिटेड की 10 गीगावाट क्षमता वाली एकीकृत इनगॉट और वेफर उत्पादन परियोजना के शिलान्यास से हुई। इस अवसर पर परियोजना के अध्यक्ष हितेशभाई दोशी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनकी छवि वाली विशेष सोलर फोटोफ्रेम भेंट की।

लीक नहीं हुआ था बोर्ड का पेपर, पैसे ऐंठने के लिए नर्सिंग छात्र ने रची थी 'फर्जी' साजिश! हुआ अरेस्ट

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पुणे में दसवीं पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ आया है. पुलिस जांच में यह सामने आया कि पेपर लीक नहीं हुआ था. इस मामले में 18 साल के चैतन्य शेंडे को चंद्रपुर से शिवाजीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक जांच में पता चला कि चैतन्य ने पेपर देने के बहाने टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर पैसे ऐंठने की साजिश रची थी.

शिक्षा मंडल को टेलीग्राम पर दसवीं के भाग एक और दो के पेपर लीक होने का संदेह होने पर उन्होंने शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत के आधार पर टेलीग्राम ग्रुप के एडमिन और सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इन सब की तलाश के लिए शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने आरोपी की तलाश शुरू की. आरोपी के चंद्रपुर में होने की जानकारी मिलते ही सभी पुलिस चंद्रपुर पहुंचे और वहां से चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया.

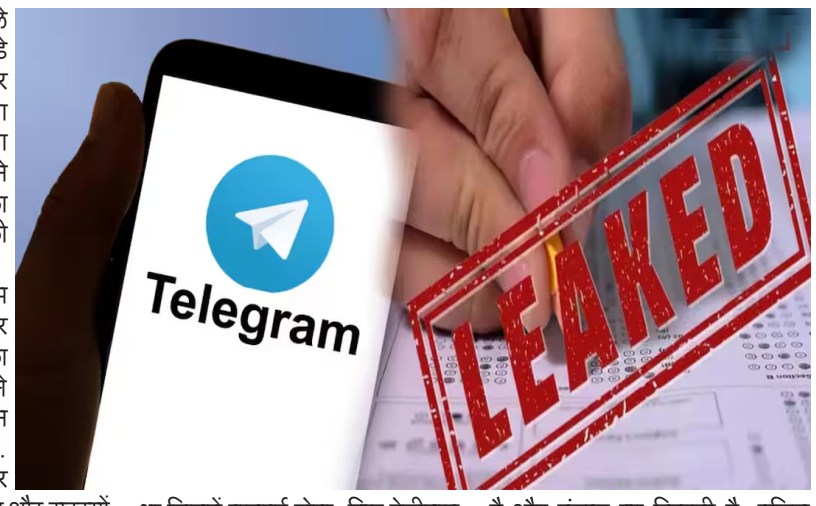

टेलीग्राम पर कैसे रची साजिश?

जांच में पता चला कि चैतन्य ने फाइल में फेरबदल कर पेपर लीक का भ्रम फैलाया. वह परीक्षा से एक दिन पहले टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड करता था जिसमें पासवर्ड होता. फिर टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज डालता कि 'मेरे पास दसवीं का पेपर है' और इच्छुक छात्रों से 600 रुपये भेजने के लिए कहता. पैसे मिलने के बाद वह नंबर ब्लॉक कर देता.

जब पेपर खत्म हो जाता, चैतन्य पीडीएफ को एडिट करके उसी दिन का पेपर अपलोड करता और सभी को यही पेपर देने का भ्रम देता. इस तरह छात्रों को झूठा भरोसा दिलाया जाता और पैसा ऐंठा जाता.

आरोपी का प्रोफाइल और पिछला रिकॉर्ड

चैतन्य शेंडे नर्सिंग के दूसरे वर्ष का छात्र है और चंद्रपुर का निवासी है. पुलिस ने बताया कि चैतन्य के साथ पहले भी इसी तरह का फ्रॉड हुआ था. पुणे के पुलिस उपायुक्त कृषीकेश रावले ने कहा कि जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि चैतन्य ने कुल कितने लोगों से पैसे ऐंठे.

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस : 'सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासी उपभोक्ता'

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी सेवाएँ प्राप्त हों तथा उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए सरकार विभिन्न पहलें लागू करती है। महाराष्ट्र में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है।

बाजार में खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं को कई बार गलत जानकारी, घटिया उत्पाद या धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में उपभोक्ताओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों की जानकारी ही उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी शक्ति है।

उपभोक्ताओं को प्राप्त छह मूलभूत अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ताओं को छह महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये अधिकार बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करते हैं।

1. सुरक्षा का अधिकार

उपभोक्ताओं को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा पाने का अधिकार है जो उनके जीवन या संपत्ति के लिए खतरा बन सकती हैं।

2. जानकारी का अधिकार

पभोक्ताओं को वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, मूल्य, घटक तथा अन्य उत्पाद संबंधी जानकारी पूरी और सही रूप में प्राप्त करने का अधिकार है।

3. चयन का अधिकार

उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्पों में से उपयुक्त वस्तु या सेवा चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जबरन बिक्री या अनुचित व्यापारिक व्यवहार निषिद्ध है।

4. सुने जाने का अधिकार

उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें उचित मंच पर रखने और उन्हें सुने जाने का अधिकार दिया गया है।

5. शिकायत निवारण का अधिकार

खराब वस्तु, दोषपूर्ण सेवा या धोखाधड़ी की स्थिति में उपभोक्ताओं को मुआवजा और न्याय पाने का अधिकार है।

6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और धोखाधड़ी से बचाव के लिए उचित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

जागरूक उपभोक्ता ही वास्तविक शक्ति

वस्तुएँ खरीदते समय उपभोक्ताओं को कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वस्तुओं पर भारतीय मानक ब्यूरो, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एगमार्क तथा आईएसओ जैसे प्रमाणन चिह्न होना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पैकेजिंग पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और अधिकतम खुदरा मूल्य अवश्य देखना चाहिए। ऑनलाइन खरीदारी करते समय केवल आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग करें और किसी को भी एक बार उपयोग होने वाला कूट या गुप्त संख्या जैसी गोपनीय जानकारी साझा न करें।

पत्रकार 'एआय' को कौशल-वृद्धि का अवसर समझें- प्रधान सचिव एवं महासंचालक ब्रिजेश सिंह

मुंबई। पत्रकारिता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि एआय को वास्तविकता समझने की क्षमता नहीं होती। सत्य की खोज और समाज का विश्वास ही पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए बदलती तकनीक के दौर में भी पत्रकारिता की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, ऐसा मत महाराष्ट्र शासन के सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय के प्रधान सचिव एवं महासंचालक ब्रिजेश सिंह ने व्यक्त किया। उन्होंने पत्रकारों से एआय को खतरे के रूप में नहीं, बल्कि कौशल-वृद्धि के अवसर के रूप में देखने का आग्रह किया।

वे मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आयोजित 'एआय परिषद 2026' के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में एआय के कारण हो रहे बदलाव, अवसर और चुनौतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष संदीप चव्हाण, उपाध्यक्ष स्वाती घोसालकर और राजेंद्र हुंजे, ट्रस्टी देवदास मटाले, अजय वैद्य तथा कार्यवाह शैलेन्द्र शिर्के सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

सिंह ने कहा कि मानव इतिहास में ज्ञान के प्रसार की प्रक्रिया छपाई तकनीक के आविष्कार के बाद व्यापक रूप से बदली। पहले ज्ञान कुछ सीमित वर्गों तक ही सीमित था, लेकिन छपाई के कारण वह आम जनता तक पहुंचा। इसके बाद प्रसार माध्यमों का विकास हुआ। जब दूरदर्शन शुरू हुआ तो अखबारों को खतरा महसूस हुआ और डिजिटल मीडिया के आने पर टीवी को खतरा लगा। इसके बावजूद समाचार पत्रों ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। भविष्य में भी पत्रकारिता बनी रहेगी, हालांकि जो कार्य स्वचालित हो सकते हैं वे एआय के कारण स्वचालित हो जाएंगे।

आज पत्रकारिता में एआय का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के कुछ हिस्सों में पूरी तरह स्वचालित 'वन-मैन न्यूज रूम' तैयार हो रहे हैं, जहां समाचार संकलन, लेखन, संपादन, फैक्ट-चेकिंग और पेज लेआउट जैसे कार्य एआय की मदद से किए जा रहे हैं। वित्त, खेल और अन्य कई क्षेत्रों की खबरें बड़ी मात्रा में स्वचालित रूप से तैयार की जा सकती हैं। इससे पत्रकारिता के कामकाज की पद्धति तेजी से बदल रही है, ऐसा उन्होंने इस अवसर पर बताया।

उन्होंने कहा कि आपकी नौकरी एआय नहीं लेगा, लेकिन एआय का उपयोग करने वाला व्यक्ति आपकी नौकरी ले सकता है। इसलिए पत्रकारों के लिए एआय कौशल सीखना बेहद जरूरी है। इस उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क महासंचालनालय की पहल पर पत्रकारों को प्रशिक्षण देने के लिए जल्द ही 'एआय इन जर्नलिज्म' नामक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि एआय के कारण ग्यान निर्माण, प्रसार और उपयोग की पूरी प्रक्रिया तेजी से बदल रही है। पत्रकारिता के कई कार्य स्वचालित हो रहे हैं और भविष्य में भी कई कार्य स्वचालित हो सकते हैं, लेकिन सत्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अंततः मानव बुद्धि पर ही रहेगी। इसलिए एआय से पत्रकारिता का स्वरूप भले बदल जाए, परंतु विश्वसनीयता, सत्यता और संपादकीय जिम्मेदारी पत्रकारिता के मूल सिद्धांत बने रहेंगे।

उन्होंने बताया कि एआय के कारण समाचार अब रियल-टाइम, तेज और हाइपर-पर्सनलाइज्ड हो रहे हैं। आज की 'अटेंशन इकॉनॉमी' में पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग रूप में सामग्री प्रस्तुत की जा रही है। कुछ विदेशी समाचार संस्थाएं एक ही खबर के कई संस्करण बनाकर अलग-अलग पाठक समूहों को भेजती हैं और यह अध्ययन करती हैं कि कौन-सा संस्करण अधिक प्रभावी है।

एआय की मदद से अब रियल-टाइम कंटेंट, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो भी तैयार किए जा रहे हैं। इससे समाचार लगातार बदलते और गतिशील रूप में उपलब्ध हो रहे हैं। जानकारी का प्रवाह अत्यंत तेज हो गया है। आज एआय के कारण एक व्यक्ति प्रतिदिन 20-30 लेख तैयार कर सकता है। हालांकि जानकारी की मात्रा बढ़ने के साथ उसकी विश्वसनीयता का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है।

उन्होंने कहा कि एआय की एक बड़ी सीमा भारतीय भाषाओं की समझ है। तकनीकी प्रगति के बावजूद एआय अभी भी मराठी सहित भारतीय भाषाओं के संदर्भ को पूरी तरह नहीं समझ पाता। अधिकांश बड़े भाषा मॉडल विकिपीडिया और रेडिट जैसे पश्चिमी स्रोतों पर आधारित हैं, जहां भारतीय अनुभव, संस्कृति और भाषाओं से जुड़ा डेटा अपेक्षाकृत कम है। इसलिए भारतीय भाषाओं के लिए स्वतंत्र एआय विकास और डेटा सार्वभौमत्व अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने यह भी बताया कि एआय आधारित प्रणालियां कभी-कभी गलत जानकारी भी उत्पन्न कर देती हैं, जिसे 'हैलुसिनेशन' कहा जाता है। ऐसे मामलों में गलत संदर्भ या तथ्य सामने आ सकते हैं। इसलिए एआय से तैयार सामग्री की अंतिम जिम्मेदारी संपादकीय स्तर पर ही रहती है।

सिंह ने कहा कि एआय के कारण डिजिटल माध्यमों में भारी मात्रा में सामग्री तैयार हो रही है, जिसे 'एआय स्लॉप' कहा जाता है। भविष्य में पत्रकारिता दो हिस्सों में बंट सकती है–एक बड़े पैमाने पर बनने वाली सामान्य खबरें और दूसरी शोध-आधारित, खोजी और उच्च गुणवत्ता वाली पत्रकारिता।

नागपुर में अफवाह का 'खूनी' खेल! बच्चा चोर समझकर 60 साल की महिला को बुरी तरह पीटा, पुलिस ने बचाया

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र के नागपुर शहर के हिंगना पुलिस थाना क्षेत्र के इसासनी इलाके में एक साठ वर्षीय वृद्ध महिला की जान सोशल मीडिया पर फैली झूठी अफवाहों के कारण जाते-जाते बची. महिला को बच्चों को चुराने वाले गिरोह का सदस्य समझकर भीड़ ने लात-घूसों से पीटा. पुलिस ने किसी तरह उसे सुरक्षित बचाया.

मिली जानकारी के अनुसार, 60 साल की महिला अस्पताल से अपनी नियमित दवा लेने के बाद घर लौट रही थी. थकान और दवा खाने के समय रुकने के कारण उसने पास के घर के सामने खेल रहे एक बच्चे से पानी मांगा. मराठी और हिंदी में ठीक से संवाद न कर पाने के कारण वृद्ध महिला अपनी बात सही तरह से नहीं रख सकी.

बैग में अपहरण का झूठा आरोप, वृद्ध महिला को पीटा गया

इसी दौरान पास में मौजूद एक महिला ने शोर मचाया कि वृद्ध महिला अपनी छोटी बेटी को बैग में डालकर अपहरण करने की कोशिश कर रही थी. इस झूठे आरोप के कारण भीड़ ने वृद्ध महिला पर हमला कर दिया. मराठी और हिंदी ठीक से न बोल पाने के कारण वृद्ध महिला अपनी रक्षा नहीं कर सकी. आरोप लगाने वाली महिला ने उसे लात-

घूसों से पीटना शुरू किया, और आसपास मौजूद लोगों को भीड़ में शामिल होने के लिए उकसाया.

बच्चों को चुराने वाले गिरोह के सक्रिय होने का झूठा और बेबुनियाद दुष्प्रचार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वृद्ध महिला को भीड़ से बचाकर सुरक्षित पुलिस स्टेशन ले गई. महिला के बेटे और बहू को बुलाकर पूरे मामले की जांच की गई.

पुलिस ने बताया कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर बच्चों को चुराने वाले गिरोह के सक्रिय होने की अफवाहें फैली हुई हैं. इसी झूठे दुष्प्रचार के कारण वृद्ध महिला को किसी ने गिरोह का सदस्य समझकर बेरहमी से पीटा.

पुलिस ने कहा कि महिला की जान सुरक्षित बच गई, लेकिन यह घटना पिछले वर्षों में नागपुर में हुई भीड़ हिंसा की घटनाओं की याद दिलाती है. 2012 में कलमना इलाके में नाथजोगी समुदाय के तीन लोग भी इसी तरह झूठे आरोपों की वजह से भीड़ द्वारा पीटकर मारे गए थे.

एक पड़ोसी के पास बिल्ली-दूसरे के पास तोता, फिर क्या हो गया लोचा! हुआ जबरदस्त एक्शन ड्रामा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बिल्ली और तोते का झगड़ा हम कई बार सुनते हैं. लेकिन पुणे में यह झगड़ा सीधे पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया. शहर के ताडीवाला रोड इलाके में बिल्ली और तोते के कारण दो पड़ोसियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि यह तूफानी मारपीट में बदल गया. इस मामले में बिल्ली के मालिक दिनेश रंगराव पोताबत्तोनी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता अभिषेक सिंह अपने परिवार के साथ ताडीवाला रोड इलाके में रहते हैं. उन्होंने अपने घर में एक तोता पाला है और उसका पिंजरा घर के सामने रखा जाता है. पड़ोसी दिनेश रंगराव पोताबत्तोनी ने एक बिल्ली पाली है, जो इलाके में खुलेआम घूमती रहती थी और अक्सर तोते के पिंजरे के पास जाकर उसका ध्यान भटकाती.

बिल्ली का शरारती अंदाज और पड़ोसियों का गुस्सा

इससे पहले भी कई बार बिल्ली ने तोते के पिंजरे को धक्का दिया था. सिंह ने कई बार पड़ोसी से बिल्ली पर ध्यान देने का अनुरोध किया, लेकिन बिल्ली को शायद पड़ोसियों की बातें सुनाई नहीं देती. घटना के दिन भी वही हुआ - बिल्ली ने तोते का पिंजरा गिरा दिया और पड़ोसियों का विवाद एकदम सुपरहिट एक्शन फिल्म जैसा शुरू हो गया.

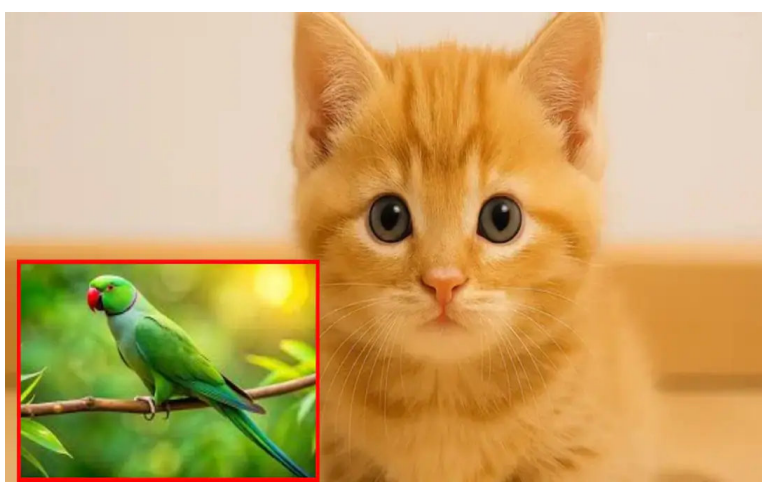

दो परिवारों की 'एक्टिंग क्लास', सड़क पर मारपीट

शुरुआत में बस थोड़ी-सी बहस हुई, लेकिन फिर दोनों परिवारों के सदस्य भी शामिल हो गए. देखते ही देखते मामला सड़क पर आ गया. लोग गाली-गलौज करने लगे, धक्का-मुक्की और मारपीट शुरू हो गई. इस मज़ेदार लेकिन दर्दनाक दृश्य में अभिषेक सिंह भी घायल हो गए.

बिल्ली और तोता बने स्टार

इस पूरे 'एविक्शन ड्रामा' के बाद अभिषेक सिंह ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने ध्यान देते हुए दिनेश रंगराव पोताबत्तोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू कर दी. अब पूरा ताडीवाला रोड इलाके में चर्चा है कि कैसे एक बिल्ली और तोते की शरारत ने पड़ोसियों को एक्शन मूवी के सीन में बदल दिया.

पुणे शहर में मामूली कारणों से विवाद बढ़ने और मारपीट जैसी घटनाओं की चिंता बढ़ रही है. वहीं सोशल मीडिया पर लोग इस घटना की तस्वीरें और वीडियो शेयर कर मज़े भी ले रहे हैं.

सम्पादकीय

खामेनेई की मौत पर मोदी की चुप्पी के कूटनीतिक मायने

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी ने कई तरह के राजनीतिक और कूटनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। अमरीका द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद भारत में ईरान के दूतावास ने दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया था कि वे अमेरिका-इजराइल द्वारा तेहरान पर किए गए हमले और उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मार दिए जाने की कड़ी निंदा करें। ईरानी दूतावास ने कहा था कि भारत स्थित इस्लामिक गणराज्य, ईरान का दूतावास दुनिया भर की आजाद और स्वतंत्रता की पक्षधर सरकारों से इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा करने तथा अराजकता एवं आक्रामकता के सामने खामोश नहीं रहने का आह्वान करता है। इसके बावजूद केंद्र सरकार की तरफ से निंदा का कोई बयान नहीं आया।

प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की निंदा करने के बजाए कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा था कि ऐसे विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। उन्होंने दोहराया कि भारत की नीति हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की रही है। सरकार का कहना है कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में बातचीत का रास्ता अपनाना जरूरी है। मोदी की तरफ से अपेक्षित बयान नहीं आने विपक्षी दल भड़क गए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की लक्षित हत्या पर मोदी सरकार की 'चुप्पी' को लेकर कहा कि उनका यह रुख भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने याद दिलाया कि कैसे पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था, जो मई 2024 में अजरबैजान में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में सात लोगों के साथ मारे गए थे। संजय सिंह ने कहा मोदी जी, आज क्या हुआ? आपने ईरान के प्रेसिडेंट की मौत पर राष्ट्रीय शोक घोषित किया था। आप ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर एक भी शोक ट्वीट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है।

भारत का किसी एक देश के लिए यह दृष्टिकोण कोई अपवाद नहीं है, बल्कि भारत की पारंपरिक विदेश नीति के सिद्धांतों के अनुरूप है–जटिल संघर्षों में प्रत्यक्ष गठबंधन से बचना और स्थिरता को प्राथमिकता देना है। भारत की प्रतिक्रिया कई वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया के समान है, जिनमें से कई ने संवेदना व्यक्त करने या सीधे तौर पर निंदा करने से परहेज किया है। इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) के 57 सदस्यों में से बहुत कम देशों ने शोक व्यक्त किया। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, इराक, तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे कुछ देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे निंदनीय बताया, जबकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने घटना को स्वीकार्य नहीं कहा। इराक में तीन दिन का शोक घोषित किया गया। हालांकि अधिकांश मुस्लिम बहुल देशों ने औपचारिक रूप से संवेदना व्यक्त नहीं की।

भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर संयम और संवाद की अपील की। साथ ही ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के सहयोगियों पर किए गए हमलों की आलोचना भी की गई। सरकार का कहना है कि भारत का रुख राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को ध्यान में रखकर तय किया गया है। गौरतलब है कि खाड़ी देशों से भारत के द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन सरकार ने इसे साम्प्रदायिक रूप देने की बात से दूरी बनाए रखी है। ऐसा नहीं है कि भारत किसी देश के मामले में ऐसा स्टैंड पहली बार लिया हो, यह रुख पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर देखा गया है, जहां भारत ने सीधे बयान देने के बजाय संतुलित कूटनीतिक भाषा का उपयोग किया है। भारत की अमरीका–ईरान युद्ध पर सतर्क भाषा रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे पूर्व के संकटों से बिल्कुल अलग है, जिनमें भारत ने प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच संबंधों को संतुलित करने का प्रयास किया था। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की फोन कॉल पर यूएई के बयान में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें संकेत दिया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी यूएई द्वारा जवाबी कार्रवाई में उठाए जाने वाले किसी भी कदम का समर्थन करते हैं। बयान में कहा गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात द्वारा अपनी संप्रभुता की रक्षा, अपनी सुरक्षा की सुरक्षा और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे सभी उपायों में भारत की एकजुटता व्यक्त की।

उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उपजे असंतोष को सूझबूझ पूर्वक पाट रहे हैं योगी आदित्यनाथ!

प्रदेश में भाजपा के संगठनात्मक पदों और सरकारी निकायों के पदों पर नियुक्तियों में विलंब मुख्य रूप से जातीय-क्षेत्रीय संतुलन, आंतरिक खींचतान और केंद्रीय नेतृत्व के मंथन के कारण हो रहा है। इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा है, हालांकि मार्च 2026 तक बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। आलम यह है कि प्रदेश के सभी 16 नगर निगम में 10-10 मनोनीत होने वाले पार्षदों की नियुक्ति अटकी पड़ी है, जबकि तीन साल बीतने को है। विभिन्न बोर्डों की भी यही स्थिति है। इससे विधानसभा चुनाव 2027 में पार्टी की रणनीति पर भी असर पड़ना लाजिमी है, क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रस्साकशी में कार्यकर्ताओं में निराशा है।

जहां तक विलंब के प्रमुख कारण की बात है तो जातीय एवं सामाजिक समीकरण इसकी पहली वजह है। भाजपा का ओबीसी करण होने से पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं में रोष गहराता जा रहा है। इसका असर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2026 में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर अवश्य पड़ेगा। लिहाजा पार्टी इससे पहले सभी वर्गों (ओबीसी, दलित, सवर्ण, खासकर ब्राह्मण राजपूत आदि) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में जुटी है, जिसपर प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के मुखिया की खींचातानी से चयन अटका हुआ बताया जाता है।

वहीं पार्टी की आंतरिक गुटबाजी जैसे सांसदों-विधायकों के बीच खींचतान और केंद्रीय नेतृत्व व आरएसएस के बीच वैचारिक मतभेद (चुनावी साख बनाम संगठन अनुभव) से कई पद लंबित हैं। वहीं, सरकारी पदों पर देरी यानी

निगमों, बोर्डों और आयोगों के 10फ़ रिक्त पदों पर पार्टी-संगठन व सरकार के बीच समन्वय की कमी, साथ ही योगी सरकार की मंजूरी का इंतजार है। अब तक ऐसा नहीं होने से जमीनी कार्यकर्ताओं में असंतोष स्वाभाविक है।

खासकर वफादार कार्यकर्ता कार्यगत पुरस्कार न मिलने, लगातार चुनावी मेहनत के बावजूद पद न पाने से नाराज हैं; जिसके चलते कतिपय जिलों में सामूहिक इस्तीफे तक हुए। योगी-केशव जैसे नेताओं के बीच अनबन की अटकलें भी असंतोष बढ़ा रही हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि पंकज चौधरी दिसंबर 2025 में प्रदेश अध्यक्ष बने, जिससे 70फ़ जिलाध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। जबकि होली के बाद मिशन-2027 के तहत नई टीम, क्षेत्रीय अध्यक्षों में बदलाव की घोषणा संभावित है, जिसके दृष्टिगत पर्यवेक्षक भेजे गए हैं।

वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं के असंतोष को कम करने के लिए संगठनात्मक बदलाव, प्रत्यक्ष संवाद, प्रशिक्षण अभियान और पदों पर समायोजन जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। ये प्रयास मुख्य रूप से 2027 चुनाव की तैयारी के तहत होली के बाद अब तेज हो रहे हैं। इस निमित्त कई संगठनात्मक कदम उठाए जा चुके हैं और कुछ प्रक्रिया धीन हैं। जहां तक नई टीम के गठन की बात है तो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में होली बाद बड़े फेरबदल, जिलाध्यक्षों-क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्तियां, जातीय संतुलन बनाकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं, सरकारी पदों पर समायोजन यानी निगमों, बोर्डों, आयोगों के खाली पदों पर कार्यकर्ताओं की सूची तैयार है, और मिशन-2027 के तहत तोहफा के रूप में वितरण कार्य शेष रहने की खबर है।

संवाद एवं प्रशिक्षण प्रयास के तहत प्रत्यक्ष मुलाकातें हो रही हैं। 'कार्यकर्ता सर्वप्रथम' मंत्र से वन-टू-वन मैपिंग, वीआईपी संस्कृति खत्म कर रूठे कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद; सीएम योगी विधायकों से नियमित बैठकें कर रहे हैं।वहीं डिजिटल एवं वैचारिक प्रशिक्षण के तहत कार्यकर्ताओं को डिजिटल हथियार से लैस करने का अभियान, और बूथ स्तर पर नीतियां-कार्यपद्धति सिखाना जारी है। आरएसएस-बीजेपी में समन्वय की कोशिशें परवान चढ़ी हुई हैं।आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से योगी की मुलाकातें, कानपुर समन्वय बैठक में असंतोष मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसके दृष्टिगत आंतरिक कलह सुलझाने की कोशिश जारी है।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी संभालने के लिए प्रत्यक्ष बैठकें शुरू कर दी है। आरएसएस-बीजेपी समन्वय मंचों पर खुली चर्चा और जमीनी मुद्दों पर आश्वासन जैसे कदम उठाए हैं। मार्च 2026 तक गोरखपुर व कानपुर जैसी जगहों पर ये प्रयास तेज हुए। प्रत्यक्ष संवाद हो रहे हैं। खुद योगी ने 200फ़ विधायकों, सांसदों व पूर्व नेताओं से अलग-अलग मुलाकातें कीं, जहां उन्होंने पार्टी की हार के कारणों (कार्यकर्ता-सरकार डिस्कनेक्ट) को सुने और विपक्षी प्रचार पर जवाब देने को कहा। साथ ही जमीनी स्तर पर समस्याओं (जैसे अस्पताल बेड) के समाधान का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री की आरएसएस से समन्वय बैठकें भी चल रही हैं। गोरखपुर (मार्च 2026) में पदाधिकारियों से मन की बात सुनकर जवाब दिए, और एआई युग व कैशलेस इलाज जैसे सवाल हल किए। वहीं कानपुर (मार्च 2026) में आरएसएस के साथ बैठक में कार्यकर्ता सम्मान, यूजीसी नियमों से सवर्ण असंतोष, स्थानीय विवादों पर चर्चा हुई; साथ ही अनुशासनहीनता पर कार्रवाई व बेहतरी का आश्वासन दिया। जबकि अन्य प्रयास के तहत बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि एसआईआर फॉर्म भरें, मतदाता जागरूकता कैंप लगाएं; और अफसरों से कार्यकर्ता शिकायतें दूर करने को कहा। साथ ही कार्यकर्ताओं से 'कैंडिड फीडबैक' भी लिया।

देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की रणनीति ने उत्तर प्रदेश भाजपा में आंतरिक एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर क्षेत्रीय समन्वय बैठकों और प्रत्यक्ष संवाद से। इससे कार्यकर्ताओं की नाराजगी घटी और 2027 चुनाव की तैयारी एकजुट हुई। वहीं क्षेत्रीय समन्वय बैठकें भी हुईं। योगी ने छह क्षेत्रों (अवध, काशी, गोरखपुर, कानपुर, ब्रज, पश्चिम) में आरएसएस-बीजेपी समन्वय बैठकें आयोजित कीं, जहां कार्यकर्ता शिकायतें (अधिकारियों का रवैया, सम्मान की कमी) सुनीं और तत्काल समाधान पर मंथन हुआ। साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लखनऊ में हुई मुलाकात ने संगठन-सरकार तालमेल बढ़ाया, जातीय समीकरणों व यूजीसी नियम विवादों को सुलझाया।

मुख्यमंत्री और आरएसएस ने जमीनी स्तर पर एकीकरण मजबूत करने पर जोर दिया। खासकर बूथ मजबूती पर जोर देते हुए एसआईआर अभियान समीक्षा, मतदाता पुनरीक्षण से कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी, वीआईपी संस्कृति खत्म कर प्रत्यक्ष फीडबैक लिया।इससे नेताओं से मुलाकातें भी तेज हुईं। योगी आदित्यनाथ 200फ़ विधायकों-सांसदों से अलग-अलग चर्चा करते हुए, पार्टी की कमजोरियां सुधारने का आश्वासन दिया। कानपुर बैठक में अनुशासन व सुधार पर बल दिया गया।परिणामस्वरूप एकता मजबूत हुई। इन प्रयासों से आंतरिक कलह कम हुई, नई संगठनात्मक टीम गठन संभव हुआ, और मिशन-2027 के लिए सभी वर्ग एकजुट हुए। वही 2024 चुनाव में मिले सबकों पर अमल होने से बूथ मजबूत हुआ।

मौन की नदी, आधुनिक समाज में रिश्तों, संवेदनाओं और सामाजिक न्याय का संकट

समय की बूढ़ी हथेली से फिसलता हुआ सत्य आज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां विजय-गाथा के कथानक युगबोध के छल में कैद हो चुके हैं। रसातल में दबे हुए यथार्थ और रश्मियों के स्वप्निल गीतों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा है, जो मौन की ठंडी नदी की तरह समाज की रग-रग में बह रहा है। जब वर्जनाएं शिशिर की तरह इतिहास को थाम लेती हैं, तब केवल प्रकृति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की चेतना भी जम जाती है। थरथराती हुई टहनियों पर लदी हिम की सुगंध दरअसल उस ठिठुरते हुए जनमानस की तरह है, जिसका इतिहास बर्फ के नीचे सहमकर और दबकर चेतना से शून्य हुआ जाता है।

शोर को गीत में बदलने की छटपटाहट और उमस से भरे दम घोंटते दिनों के बीच लयों का नवनीत खोजना ही वह संघर्ष है, जो मानवीय संबंधों को फिर से परिभाषित करता है। संबंधों की ऊष्मा जब नेह भीगी रागिनी में तब्दील होती है, तभी समाज का कसैलापन स्निग्धता से आच्छादित प्रीत में बदल पाता है। मगर आज के परिवेश में मानवीय संबंधों की स्थिति उस पंख टूटी सांझ की तरह हो चली है, जो वन में भटककर खो गई है।

समय की हथकड़ी पहने हुए लोग जब निर्वासन पर निकलते हैं, तो परिचय की चूड़ियां पहले ही टूटकर बिखर जाती हैं। स्मृतियों की परत पर जमी हुई दूरियां जब तक सांसों में उभरती हैं, तब तक संवाद के विहग अनजान नभ में उड़ जाते हैं।

ऐसे में सामाजिक न्याय का प्रश्न तब और गहरा हो जाता है, जब कथा जन-अभिषेक की हर बार अधूरी रह जाती है। संकल्प की छिदती हुई त्वचा और गरलदंतों के प्रहार से सत्ता और व्यवस्था के नागपाशों मंज केवल कल्पनाएं ही नहीं, बल्कि मनुष्य का आत्मसम्मान भी जकड़ कर चेतनाहीन हुआ है। सिसकते हुए सीवानों पर गांव दर गांव का जो दर्द पसरा है, वह इसी सामाजिक विषमता की उपज है, जहां रश्मियों के गीत स्वप्निल राख की ढेरी बनकर रह गए हैं।

क्षितिज पर दो रश्मि की ऋचाएं टांकने की कोशिशें उन धुंधली दिशाओं में रास्ता खोज रही हैं, जहां काजल नहीं बुहरा है और अंधेरों की दीवारें बहुत ऊंची हो गई हैं। देहरी का पथरा जाना और रोशनी की बाट जोहते-जोहते आंखों का कुहरा जाना उस लंबी प्रतीक्षा का प्रमाण है, जो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए की जा रही है। सलीबों पर टंगे फूलों और भीड़ के पहियों तले कुचले हुए पंखों का कुहरा स्पष्ट करता है कि व्यवस्था की चक्की में कोमल न्याय की मानवीय संवेदनाएं पिस कर रह गई हैं। पांव और पंख के बावजूद मंजिल का न दिखना उस संवेदनहीन शून्यता को दर्शाता है, जहां आधुनिक मनुष्य अपने ही बनाए तंत्र में लगभग पराया हो गया है। यहां युग-यती का सो जाना और नेकी-नदी को भूल जाना उस नैतिक पतन का परनाला है, जो हमारे समाज के लिए आत्मघाती बनता जा रहा है।

ऐसे में मानवीय संबंधों के सृजन की प्यास ही वह एकमात्र तत्त्व है, जो इस बिखराव को जोड़ सकती है। जो गीत कल मेज पर अधलिखा छोड़ दिया गया था, उसमें नया छंद जोड़ना दरअसल टूटे हुए मानवीय संबंधों को फिर से युवा करने की प्रक्रिया है। अगर इसी को पहचान लिया जाए, इसी को थोड़ा बचा लिया जाए, तो उम्मीद की रोशनी एक बार फिर जिंदगी का जरिया बन सकती है।

चांदनी की गंध से आकाश को भरने का स्वप्न तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब न्याय के सहारे खड़ा होकर मौन वाचाल हो जाए। कुमुदिनी-सा खिला हुआ देह का छवि-ताल और चुप्पियों के पास सजे संबोधन ही वे सेतु हैं, जो व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं।

जब शब्द खो जाते हैं और अनसुनी, अनकही कहानी शेष रह जाती है, तब कल्पना-सी रातरानी की तरह स्मृतियां ही पास आकर सटती हैं।

सामाजिक न्याय का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक होगा, जब धधकते विद्रोह के स्वर बर्फ के नीचे से निकलकर मुखर हों और सरिता की तरंगों पर रागिनी का कुमकुम फिर से रचा जाएगा। विकास की अंधी दौड़ में जो पांव थक चुके हैं और जो पंख नागपाशों में जकड़े हुए हैं, वहां भूखे को न्याय के निवाले चाहिए।

आधुनिकता के नाम पर जो संबंध कल मेज पर अधलिखे छोड़ दिए गए थे, आज वे अपनी पहचान के लिए छटपटा रहे हैं। विडंबना यह है कि जिन संबंधों से दूरी या उनका अभाव हमें अक्सर परेशान करता है, हम उसे फिर से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन की नई परिभाषाएं हमें अपने खोखले दायरे पर ही गर्व करना सिखा चुकी होती हैं।

ज्योतिपंख गीत जब तक मौन रहेंगे, तब तक दिशाएं धूमिल ही रहेंगी। मानवीय संवेदनाओं का घायल पोर आज यह सवाल पूछता है कि क्या सृजना की यह थरथराहट केवल दर्द तक सीमित रहेगी या फिर यह किसी नए वसंत की आहट बनेगी।

मौन की ठंडी नदी और धूप से दहके हुए दिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ओर जहां पंख टूटी सांझ वन में भटककर खो जाते हैं, दूसरी ओर क्रांतिवाही स्वर बर्फ के नीचे दबकर भी अपनी गर्मी नहीं खोते। यह पूरा परिवेश उस सृजनात्मक संघर्ष का है, जहां स्मृतियों के गलियारे में पारे की तरह फिसलता सत्य अपनी पहचान ढूंढ़ रहा है। ऐसे में संकल्प ही जीवन की सार्थकता है कि किस प्रकार भीतरी स्निग्धता से बाहरी कोलाहल को शांत किया जाए और किस प्रकार अधूरी कथाओं को संकल्प की पूर्णता तक पहुंचाया जाए।

क्या केवल आईएएस से बदलेगा देश?

(प्रशासन व्यवस्था जरूरी, पर असली परिवर्तन नवाचार, विज्ञान और दूरदर्शी विचारों से आता है।)

देश की दिशा बदलने वाले विचार अक्सर प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, खेतों और उद्योगों से आते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था उन विचारों को लागू करने और उन्हें व्यापक स्तर पर पहुँचाने में मदद करती है, परंतु मूल विचार का जन्म अक्सर किसी वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्यमी या सामाजिक कार्यकर्ता के मन में होता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रशासनिक सेवा और नवाचार की भूमिका अलग-अलग होते हुए भी एक-दूसरे की पूरक हैं।

– डॉ. प्रियंका सौरभ

भारत में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा केवल एक प्रतियोगी परीक्षा नहीं रह गई है, बल्कि यह आज के युवाओं के लिए प्रतिष्ठा, शक्ति और सामाजिक सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। हर वर्ष लाखों युवा इस परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं और इसके साथ-साथ एक विशाल कोचिंग उद्योग भी खड़ा हो चुका है, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये आँकी जाती है। माता-पिता अपने बच्चों को बचपन से ही यह सपना दिखाने लगते हैं कि वे बड़े होकर प्रशासनिक अधिकारी बनें। समाज में भी प्रशासनिक सेवाओं को इतनी प्रतिष्ठा दी जाती है कि यह कई युवाओं के लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है।

इसी वातावरण के बीच हाल ही में एकप्रसिद्ध शिक्षक का एक वक्तव्य व्यापक चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवा का अधिकारी देश को नहीं बदल सकता। उनके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी एक अच्छे कार्यान्वयनकर्ता होते हैं, जिनका मुख्य कार्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को जमीन पर लागू करना होता है। लेकिन जब बात नए विचारों, बड़े परिवर्तन और ऐतिहासिक उपलब्धियों की आती है, तो इतिहास में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं जहाँ किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई क्रांतिकारी दिशा दी हो। यह कथन कई लोगों को कठोर लगा, परंतु इसने एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है–क्या सचमुच देश का भविष्य केवल प्रशासनिक सेवाओं से तय होता है या उसके पीछे वैज्ञानिकों, विचारकों और नवाचार करने वालों की बड़ी भूमिका होती है?

यदि हम भारत के इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएँगे कि देश को दिशा देने वाले कई बड़े परिवर्तन प्रशासनिक ढाँचे से बाहर के लोगों ने किए। भारत का परमाणु कार्यक्रम हो या अंतरिक्ष अनुसंधान, हरित क्रांति हो या श्वेत क्रांति–इन सभी के पीछे दूरदर्शी वैज्ञानिकों और सामाजिक उद्यमियों की भूमिका रही है। होमी जे भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी और यह दिखाया कि विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को मजबूत किया जा सकता है। विक्रम सारा भाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की और आज भारत विश्व के अग्रणी अंतरिक्ष देशों में गिना जाता है।

इसी प्रकार अब्दुल कलाम ने मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया और भारत को सामरिक रूप से मजबूत बनाया। कृषि क्षेत्र में स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना। वहीं वर्घीस कुरियन ने अमूल आंदोलन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाकर लाखों किसानों की आर्थिक स्थिति बदल दी।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि देश की दिशा बदलने वाले विचार अक्सर प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों, खेतों और उद्योगों से आते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था उन विचारों को लागू करने और उन्हें व्यापक स्तर पर पहुँचाने में मदद करती है, परंतु मूल विचार का जन्म अक्सर किसी वैज्ञानिक, शिक्षक, उद्यमी या सामाजिक कार्यकर्ता के मन में होता है।

फिर भी यह भी उतना ही सत्य है कि प्रशासनिक सेवाओं का महत्व कम नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीतियों को लागू करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनता तक योजनाओं को पहुँचाने के लिए सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होती है। यदि कोई महान वैज्ञानिक कोई नई तकनीक विकसित करता है, तो उसे समाज तक पहुँचाने के लिए प्रशासनिक ढाँचे की सहायता आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए हरित क्रांति का विचार वैज्ञानिकों ने दिया, लेकिन उसे देश भर में लागू करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसी प्रकार दुग्ध सहकारिता आंदोलन को भी व्यापक रूप देने में सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों ने सहयोग किया। समस्या तब उत्पन्न होती है जब

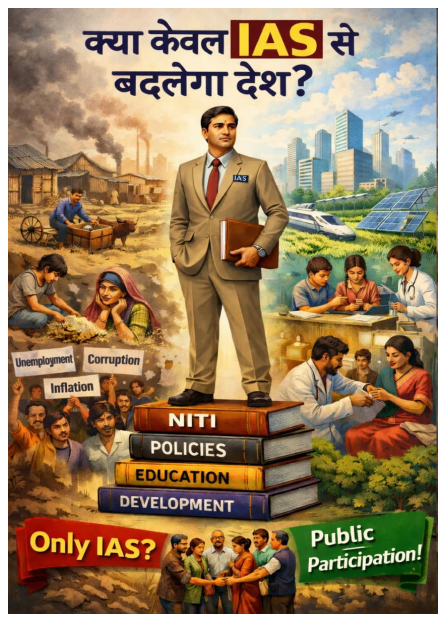

समाज किसी एक ही पेशे को सफलता का अंतिम प्रतीक मानने लगता है। भारत में प्रशासनिक सेवाओं को लेकर यही स्थिति देखने को मिलती है। अनेक प्रतिभाशाली छात्र जो विज्ञान, शोध, उद्यमिता या कला के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दे सकते हैं, वे भी अंततः प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लग जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिभा का प्रवाह कम हो जाता है। देश को जितनी आवश्यकता अच्छे प्रशासकों की है, उतनी ही आवश्यकता उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, शिक्षकों, चिकित्सकों, अभियंताओं और उद्यमियों की भी है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रशासनिक सेवा को अक्सर शक्ति और अधिकार के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। समाज में यह धारणा बन गई है कि प्रशासनिक अधिकारी बनते ही व्यक्ति के पास अपार शक्ति आ जाती है। यह धारणा युवाओं को आकर्षित करती है, लेकिन इससे सेवा की वास्तविक भावना पीछे छूट जाती है। प्रशासनिक सेवा का मूल उद्देश्य समाज की सेवा करना और जनता की समस्याओं का समाधान करना है, न कि केवल अधिकारों का उपयोग करना। यदि युवा केवल शक्ति और प्रतिष्ठा के आकर्षण में इस क्षेत्र में आते हैं, तो वे प्रशासनिक व्यवस्था को उतना प्रभावी नहीं बना पाते जितनी अपेक्षा की जाती है।

खान सर का वक्तव्य इसी मानसिकता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। उनका उद्देश्य शायद प्रशासनिक सेवाओं की आलोचना करना नहीं, बल्कि युवाओं को यह समझाना है कि राष्ट्र निर्माण के अनेक रास्ते होते हैं। यदि कोई युवा वैज्ञानिक बनता है, नई तकनीक विकसित करता है, कोई सामाजिक मॉडल बनाता है या कोई सफल उद्योग स्थापित करता है, तो उसका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी प्रशासनिक अधिकारी का। वास्तव में कई बार ऐसे नवाचार ही प्रशासनिक नीतियों को दिशा देते हैं।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के विकास के लिए बहुआयामी प्रतिभाओं की आवश्यकता है। केवल प्रशासनिक सेवा के माध्यम से ही देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और संस्कृति–इन सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रतिभा और समर्पण की जरूरत है। यदि देश के अधिकांश प्रतिभाशाली युवा केवल एक ही लक्ष्य की ओर दौड़ने लगेंगे, तो अन्य क्षेत्रों में संतुलन बिगड़ सकता है।

आज दुनिया तेजी से बदल रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नए-नए अवसर और चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। भारत यदि वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनना चाहता है, तो उसे शोध और नवाचार पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि युवा नई खोजों और प्रयोगों की ओर भी उतनी ही रुचि से बढ़ें जितनी रुचि वे प्रशासनिक सेवाओं में दिखाते हैं। यह भी आवश्यक है कि शिक्षा व्यवस्था छात्रों को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक सीमित न करे, बल्कि उन्हें जिज्ञासु, रचनात्मक और प्रयोगशील बनाए। यदि विद्यालय और विश्वविद्यालय छात्रों में नवाचार की भावना विकसित करेंगे, तो वे केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी प्रेरित होंगे। इसी प्रकार समाज को भी यह समझना होगा कि सफलता का अर्थ केवल एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने कार्य के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। अंततः यह कहना उचित होगा कि प्रशासनिक अधिकारी और नवाचार करने वाले दोनों ही राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एक ओर जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था नीतियों को लागू करती है और व्यवस्था बनाए रखती है, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक, विचारक और उद्यमी नए रास्ते खोलते हैं। यदि इन दोनों के बीच संतुलन और सहयोग हो, तो देश की प्रगति अधिक तेज और स्थायी हो सकती है।

युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी रुचि, क्षमता और जुनून के अनुसार अपना मार्ग चुनें। यदि किसी को प्रशासनिक सेवा में रुचि है, तो उसे पूरी निष्ठा के साथ उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि कोई युवा विज्ञान, शोध, उद्यमिता या कला के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहता है, तो उसे भी उतना ही सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

राष्ट्र निर्माण का कार्य किसी एक पद या पेशे तक सीमित नहीं होता। यह एक सामूहिक प्रक्रिया है, जिसमें हर क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण होता है। जब समाज प्रशासनिक सेवा के साथ-साथ नवाचार, शोध और उद्यमिता को भी समान महत्व देगा, तभी भारत वास्तव में ज्ञान, विज्ञान और प्रगति की दिशा में एक सशक्त राष्ट्र बन सकेगा।

जनपद न्यायाधीश ने माल्यार्पण व द्वीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का किया शुभारंभ

भदोही ।माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही-ज्ञानपुर के तत्वाधान में एवं जनपद न्यायाधीश श्री अखिलेश दूबे के कुशल मार्गदर्शन में जनपद न्यायाधीश 14 मार्च दिन शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से जनपद न्यायालय परिसर सरपतहों ज्ञानपुर के सभागार कक्ष में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत के अवसर पर कहा गया कि लोक अदालत मामलों के निस्तारण का सस्ता एवं समुचित साधन है जिसके माध्यम से मामले त्वरित गति से निस्तारित हो जाते हैं इसमें किसी प्रकार की ना तो हार होती है ना तो जीत। मामले अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा दीवानी न्यायालय परिसर का भ्रमण कर वादकारियों से भी उनकी समस्यायें सुनी गयी तथा न्यायिक अधिकारियों व बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आमजन के मामलों को निस्तारित करें जिससे आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का लाभ मिल सके तथा लोक अदालत की संकल्पना साकार हो सके। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय भदोही, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, व समस्त न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, अग्रणी जिला प्रबन्धक यूनियन बैंक व बैंक के अन्य कर्मचारी, जनपद न्यायालय के कर्मचारीगण, व पत्रकार आदि उपस्थित रहें। लोक अदालत में निस्तारण हेतु कुल 68,853 मामले सन्दर्भित किये गये व कुल 56,696 मामलों का निस्तारण किया गया। आपराधिक मामलों में कुल रू0- 8,00,9977 अर्थदण्ड वसूल किये गये। सक्सेसन के मामले में कुल रू0 778227 रूपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये गये तथा बैंक के प्री लिटिगेशन मामलों में कुल 52,55,3305 रूपये वसूले गये। एन0आई0 एक्ट के मामलों में कुल 150000 रूपये समझौता धनराशि तय की गयी। बिजली बिल बकाया सम्बन्धित मामलों में रूपया 211.11 लाख की समझौता धनराशि तय की गयी।

निस्तारित मामलों में श्री अखिलेश दूबे, जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा कुल 03 मामले, श्री रत्नेश मणि त्रिपाठी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के द्वारा कुल 68 वैवाहिक मामले व श्री बंश बहादुर यादव पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भदोही के द्वारा कुल 14 मामले. श्री पवन कुमार तिवारी अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत द्वारा कुल 02 मामले, श्रीमती पुष्पा सिंह, अपर जिला जज प्रथम द्वारा कुल 01 मामले, श्री अमित वर्मा, अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट. द्वारा कुल 130 मामला, श्री आनन्द कुमार मिश्रा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कुल 1047 मामले, श्री आशीष कुमार सिंह अपर मुख्य न्यायिक मजि0 द्वारा कुल 539 मामले, सुश्री अनामिका चौहान सिविल जज सी0डि0 द्वितीय द्वारा कुल 216 मामले, श्री अमित कुमार सिंह, सिविल जज, सी0डि0, तृतीय, द्वारा कुल 604 मामले, श्री शहनवाह अहमद सिद्दकी सी0डि0 त्वरित न्यायालय द्वारा कुल 29 मामले, श्री बलराम पनवार सिविल जज जू0डि0 के द्वारा कुल 23 मामले, श्रीमती कमलेश कुमारी सिविल जज जू0डि0 प्रथम द्वारा कुल 11 मामले, श्री अरिजीत सिंह, न्यायिक मजि0 द्वितीय द्वारा कुल 1291 मामले, अपर सिविल जज जू0डि0 द्वितीय के द्वारा कुल 106 मामले, सिविल जज जू0डि0 चतुर्थ के द्वारा कुल 56 मामले, अपर सिविल जज जू0डि0 त्वरित न्यायालय के द्वारा कुल 27 मामले, अपर सिविल जज जू0डि0 एफटीसी महिला उत्पीड़न के द्वारा कुल 25 मामले, निस्तारित किये गये। लोक अदालत में अपर जिला जज / पॉक्सो प्रथम श्री लोकेश कुमार मिश्रा द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। बैंक प्रिलिटिगेशन के कुल 816 मामले निस्तारित किये गये तथा प्रशासनिक / राजस्व के कुल 51072 मामलों को निस्तारित किया गया व रू0 907000 अर्थदण्ड वसूले गये।

माननीय जिला जज महोदय द्वारा लोक अदालत की सफलता हेतु श्रीमती पुष्पा सिंह अपर जिला जज प्रथम को राष्ट्रीय लोक अदालत का नोडल अधिकारी नामित किया गया तथा बैंक के एन0पी0ए0 खातों के बैंक लोन रिकवरी के मामलों के निस्तारण हेतु प्री-लिटिगेशन स्तर पर लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमे मामलों के निस्तारण हेतु माननीय जिला जज महोदय द्वारा एक लोक अदालत पीठ का गठन किया गया। पीठ के अध्यक्ष श्रीमती अपर जिला जज प्रथम व सदस्य श्रीमती तरूणिमा पाण्डेय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भदोही नियुक्त किये गये। उक्त पीठों द्वारा बैंक के 816 मामले प्रीलिटिगेशन स्तर पर निस्तारित किये गये जिसमें रू0 52553305/- समझौता धनराशि तय की गयी। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही के कर्मचारीगण श्री अविनाश कुमार सहा0 लिपिक, श्री दीपक गौतम सहा0 लिपिक, श्री राजेश कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।

मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, मंडलायुक्त ने फार्म-07 की सुपर चेकिंग कर दिए निर्देश

कलेक्ट्रेट सभागार में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भदोही एवं औराई से संबंधित फार्म-07 की कार्यवाही की गहन समीक्षा की। इस दौरान प्राप्त फार्मों की जांच के साथ-साथ उनके स्थलीय परीक्षण की भी समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित बीएलओ, सुपरवाइजर और ईआरओ भी उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से बिना पर्याप्त जांच के नहीं काटा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से प्राप्त होने वाले सभी फार्मों की गंभीरता से जांच की जाए तथा नाम अपमार्जन की कार्रवाई से पहले संबंधित स्थल का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। साथ ही कम से कम दो गवाहों के बयान लेने के बाद ही नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि किसी पात्र मतदाता के अधिकारों का हनन न हो। मंडलायुक्त ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को निर्देशित किया कि वे स्वयं क्षेत्र में जाकर फार्मों का परीक्षण कराएं और प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निर्धारित समय के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध एवं पारदर्शी होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस दौरान समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, उप जिलाधिकारी औराई श्यामामणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरि, सहायक निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव सहित बीएलओ, सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में प्रवेश के लिए ट्रायल्स 2 मार्च से, खिलाडी करे आवेदन

ज्ञानपुर। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश, खेल भवन लखनऊ के सौजन्य से प्रदेश में संचालित आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रवेश हेतु खिलाड़ियों के चयन के लिए जिला एवं मंडल स्तरीय ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे। यह ट्रायल्स स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिला खेल कार्यालय भदोही में प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होंगे। जिला स्तरीय ट्रायल्स के अंतर्गत बालक वर्ग में जिम्नास्टिक, तैराकी, कुश्ती, हॉकी, वॉलीबाल, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के लिए 2 मार्च 2026 तथा बालिका वर्ग के लिए 24 मार्च 2026 को चयन परीक्षण होगा। वहीं बालक वर्ग के क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबाल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो और हैंडबॉल के ट्रायल्स 25 मार्च को तथा बालिका वर्ग के कबड्डी, बास्केटबाल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स व हैंडबॉल के ट्रायल्स 26 मार्च को आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार मंडल स्तरीय ट्रायल्स में बालक वर्ग (जिम्नास्टिक, तैराकी, कुश्ती, हॉकी, वॉलीबाल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस) के लिए 27 मार्च तथा बालिका वर्ग के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है। बालक वर्ग के क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबाल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो और हैंडबॉल के मंडलीय ट्रायल्स 29 मार्च को तथा बालिका वर्ग के लिए 30 मार्च को आयोजित होंगे। आयु सीमा के अनुसार जिम्नास्टिक और तैराकी के लिए खिलाडियों की आयु 12 वर्ष से कम तथा अन्य खेलों के लिए 15 वर्ष से कम होना अनिवार्य है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक खिलाड़ियों को खेल साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित शुल्क बैंक या कोषागार में जमा करना होगा तथा फॉर्म पर संबंधित क्रीड़ा अधिकारी या उप क्रीड़ाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। ट्रायल्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को फिजिकल टेस्ट में 50 में से कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। फिजिकल टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों को ही स्किल टेस्ट में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ी ही मंडल स्तर पर भेजे जाएंगे और मंडलीय स्तर पर चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला एवं मंडल स्तर के ट्रायल्स में खिलाड़ियों को अपने खर्च पर भाग लेना होगा, जबकि मंडलीय टीम में चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजने का समस्त खर्च खेल विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को 15 दिवसीय केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिसका पूरा व्यय भी खेल विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

श्री कृष्णापुरम गद्दोपुर में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन आज

फाफामऊ अखिल भारतीय श्री कृष्णा चेतना संस्थान, श्री कृष्णापुरम गद्दोपुर फाफामऊ द्वारा रविवार 15 मार्च को वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम दोपहर 1:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित किया जाएगा।संस्था के अध्यक्ष जय नाथ यादव, महासचिव रामकुमार यादव तथा कोषाध्यक्ष डॉ. धर्मराज यादव ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत सद्भावना मिलन एवं वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का विशेष आयोजन किया जाएगा। इसमें क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा तथा समाज में उनके योगदान को सराहा जाएगा।संस्था के पदाधिकारियों ने क्षेत्र के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होकर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान बढ़ाने की अपील की है। कार्यक्रम में सामाजिक, शैक्षिक एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग भी भाग लेंगे।

कोनिया क्षेत्र में बढ़ा म'छरों का प्रकोप, ग्रामीणों ने दवा छिड़काव की उठाई मांग

सीतामढ़ी । डीघ ब्लाक के कोनिया क्षेत्र में गंगा किनारे बसे गांवों और मोहल्लों में इन दिनों म'छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। क्षेत्र के लगभग सभी गांवों से यह शिकायत लगातार मिल रही है कि शाम होते ही म'छरों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा किनारे बसे होने के कारण क्षेत्र में नमी अधिक रहती है, जिससे म'छरों के पनपने की संभावना भी ज्यादा रहती है। शाम होते ही म'छरों का झुंड घरों और गलियों में दिखाई देने लगता है, जिससे ब'चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। रात में सोना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि म'छरों के बढ़ते प्रकोप से मलेरिया, डेंगू और वायरल बुखार जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में समय रहते प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाना बेहद जरूरी है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि कोनिया क्षेत्र के गंगा किनारे बसे सभी गांवों में तत्काल प्रभाव से घर-घर दवा का छिड़काव कराया जाए। साथ ही नियमित रूप से फॉगिंग की व्यवस्था भी की जाए, ताकि म'छरों पर नियंत्रण पाया जा सके। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर राहत दिलाने की मांग की है।

पीएम किसान की 22वीं किस्त जारी, किसानों के खातों में भेजी गई राशि-दीपक मिश्रा

ज्ञानपुर। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय ज्ञानपुर में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने बताया कि 1 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी असम से प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत देशभर के किसानों के खातों में 18,640 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। उन्होंने बताया कि इस बार 9 करोड़ 2 लाख से अधिक पात्र किसानों को आर्थिक सहायता का लाभ मिला है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व वाली सरकार लगातार जनता के हित में कार्य कर रही है और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। वहीं जिला प्रभारी नागेंद्र रघुवंशी ने बताया कि इस किस्त के जारी होने के बाद योजना के तहत अब तक देश के किसानों को कुल 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जनपद भदोही में किसान सम्मान निधि के लगभग 1.82 लाख लाभार्थी किसानों को 22वीं किस्त का लाभ मिला है। किसानों के खातों में करीब 7.5 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई है।

कमिश्नर व आईजी ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, पारदर्शिता से परीक्षा कराने के निर्देश

भदोही। विंध्याचल मंडल मिर्जापुर के मंडलायुक्त राजेश प्रकाश, पुलिस महानिरीक्षक आर.पी. सिंह, जिलाधिकारी शैलेष कुमार तथा पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने शनिवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर में आयोजित उपनिरीक्षक पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने परीक्षा व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, अभ्यर्थियों की सुविधाओं तथा तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिया कि परीक्षा का आयोजन पूरी पारदर्शिता, शुचिता और निष्पक्षता के साथ कराया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने पाए।

आईजी आर.पी. सिंह ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है और केंद्रों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित हों।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि परीक्षा को सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। प्रवेश द्वारों पर सघन जांच तथा सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई है।

इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, परीक्षा केंद्र के प्रभारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

पीपरगांव में मृतक चौकीदार के परिजनों से मिले लोजपा सांसद अरुण भारती, न्याय का दिलाया भरोसा

ज्ञानपुर। थाना ज्ञानपुर क्षेत्र के ग्राम सभा पीपरगांव में मृतक चौकीदार के परिजनों से मिलने शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।

बताया जाता है कि 9 मार्च 2026 की सुबह करीब 7 बजे पीपरगांव निवासी जैसलाल सरोज (55) ग्राम प्रधान के यहां हैंडपंप ठीक कराने की बात कहने गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान ग्राम प्रधान के पुत्र ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

सांसद अरुण भारती ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने क्षेत्राधिकारी से फोन पर वार्ता कर पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा आवासीय पट्टा देने की मांग की। साथ ही पुलिस अधीक्षक से भी बातचीत कर मामले में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति (पासी) परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में कमला कुमारी, राजीव पासवान एडवोकेट, कमल तिवारी, विकास पांडेय, धनंजय दुबे, विकास दुबे, राहुल तिवारी, संतोष पंडित, प्रदुम्न तिवारी, अभिनव तिवारी, शिवांश मिश्रा, सूरज गुप्ता, अमित शुक्ला, दुर्गेश मिश्रा, सुनील जायसवाल, विजय पाल सरोज, नंद कुमार सोनी, महेश पांडेय, सभाशंकर दुबे, विनीत सिंह, विजय राय, गोविंद पासवान, राज नीरज सिंह, गुरु प्रसाद राणा, विशाल सिंह, आशीष पासवान, आशुतोष सिंह गहरवार, छोटे लाल पासवान, सीमा सिंह, शिवम मिश्रा, अवनीश तिवारी, अजीत पासवान, विपिन शुक्ला, योगेश पांडेय, धीरज चतुर्वेदी, आदेश चतुर्वेदी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

2019 बैच के आईपीएस अभिनव त्यागी होंगे भदोही के नए एसपी

भदोही।भदोही। उत्तर प्रदेश शासन ने शुक्रवार देर शाम भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसी क्रम में भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक का स्थानांतरण फतेहपुर जनपद कर दिया गया है।

अब भदोही की कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी आईपीएस अभिनव त्यागी को सौंपी गई है। वह जल्द ही जनपद भदोही में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे।

नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी मूल रूप से आगरा के निवासी हैं। उन्होंने बीटेक साइंस से उच्च शिक्षा प्राप्त की है और वह वर्ष 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

भदोही आने से पहले अभिनव त्यागी कुशीनगर और गोरखपुर में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें तेज-तर्रार कार्यशैली और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जाना जाता है।

दहेज प्रथा समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप-संदीप तिवारी

एनएसएस विशेष शिविर के चौथे दिन स्व'छता और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चलाया गया जागरूकता अभियान

ज्ञानपुर। श्री घनश्याम दूबे महाविद्यालय, सुरियावां भदोही में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय विशेष शिविर के चौथे दिन शनिवार को स्वयंसेवकों ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। ग्राम सचिवालय कुसौड़ा, सुरियावां में कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आलोक श्रीवास्तव के निर्देशन में सुबह व्यायाम और योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तीनों इकाइयों के स्वयंसेवक-स्वयंसेविकाओं के साथ गांव के युवाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। नाश्ते के बाद प्रथम इकाई के स्वयंसेवक-स्वयंसेविकाओं ने कार्यक्रम अधिकारी सूर्य प्रकाश पाठक के नेतृत्व में सहोदरपुर मलिन बस्ती में साफ-सफाई अभियान चलाया और लोगों को स्व'छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। द्वितीय इकाई के स्वयंसेवक-स्वयंसेविकाओं ने कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आलोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में कुसौड़ा बाईपास वार्ड नंबर-1 मलिन बस्ती में सफाई अभियान चलाकर स्व'छता से होने वाले लाभों की जानकारी दी। वहीं तृतीय इकाई के स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सूर्य प्रकाश उपाध्याय के साथ कुसौड़ा मलिन बस्ती में साफ-सफाई करते हुए लोगों को बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। दोपहर के भोजन के बाद आयोजित बौद्धिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाविद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य गोरख गुप्ता ने दहेज एक सामाजिक अभिशाप विषय पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दहेज प्रथा के कारण समाज में कई बेटियों के विवाह में कठिनाई आती है और इसके चलते उन्हें मानसिक व शारीरिक उत्पीड़ का सामना भी करना पड़ता है। कार्यक्रम में वक्ता संदीप कुमार तिवारी ने कहा कि दहेज प्रथा समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इस पर सख्ती से कानूनी रोक लगनी चाहिए और दहेज लेने वालों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, तभी इस कुरीति पर रोक संभव है। उन्होंने कहा कि शिक्षित समाज के लिए यह एक बड़ा कलंक है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय कुमार पाण्डेय, कार्यक्रम अधिकारी डॉ. आलोक श्रीवास्तव, डॉ. सूर्य प्रकाश उपाध्याय, सूर्य प्रकाश पाठक, पंकज दूबे, संतोष यादव, संदीप तिवारी, विपिन पाठक, अनिल यादव, चंद्रकला अग्रहरि, अंजली पाठक, प्रीति पाठक, सौरभ, कमलेश राय, प्रमोद शर्मा, अभिषेक गुप्ता, महेंद्र यादव, सोनी, दीनदयाल उपाध्याय, गीता सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

रसोई गैस की किल्लत की अफवाहों पर ध्यान न दें: जिलाधिकारी

ज्ञानपुर। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा है कि जिले में रसोई गैस की किल्लत को लेकर फैल रही भ्रामक एवं अपुष्ट खबरों पर ध्यान न दें और न ही ऐसी अफवाहों को फैलाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनपद में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी होने की स्थिति नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर गैस की कमी को लेकर गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जो पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने जनपदवासियों से अनुरोध किया कि ऐसी अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें।

सांसद कार्यालय में होली मिलन समारोह, मंडल अध्यक्षों का हुआ सम्मान

भदोही। गोपपुर गोपीगंज स्थित सांसद डॉ. विनोद बिंद के कार्यालय पर शनिवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों सहित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

इस अवसर पर सांसद डॉ. विनोद बिंद ने कहा कि होली मिलन समारोह हमारी सामाजिक एकता को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज विभिन्न विचारधाराओं के बावजूद एकजुट होकर सामाजिक समरसता और एकता की मिसाल कायम करता है।

सांसद ने कहा कि होली का पर्व हमें आपसी गिले-शिकवे भुलाकर प्रेम और भाईचारे के साथ जोड़ता है तथा हमारी सांस्कृतिक एकता को और मजबूत बनाता है।

कार्यक्रम के दौरान सांसद डॉ. विनोद बिंद ने सभी मंडल अध्यक्षों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और होली की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को अबीर-गुलाल लगाकर पर्व की खुशियां साझा कीं।

गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर छापा, 84 सिलेंडर जब्त

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ शिधावाटप विभाग के भरारी दस्ते ने भिवंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। इस मामले में दो टेम्पो चालकों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार ठाणे उपनियंत्रक शिधावाटप (एफ परिमंडल) कार्यालय के उपनियंत्रक प्रशांत काले के मार्गदर्शन में गठित भरारी पथक को सूचना मिली थी कि भिवंडी तालुका के वलपाडा इलाके में एक गोदाम में अनधिकृत रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा है। सूचना के आधार पर निरीक्षक भगवान खंडेराव के नेतृत्व में टीम ने भिवंडी शिधावाटप अधिकारी रत्नदीप सावंत, गणेश हरने और मनीष शास्त्री के साथ मिलकर वर्धमान कंपाउंड, वलपाडा में छापा मारा। छापेमारी के दौरान वहां खड़े तीन टेम्पो से कुल 84 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। जब्त सिलेंडरों में भारत गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गो गैस और गैस वन कंपनियों के 4, 12, 17 और 19 किलो वजन के घरेलू तथा व्यावसायिक सिलेंडर शामिल हैं। इनमें 51 खाली और 33 भरे हुए सिलेंडर पाए गए। अधिकारियों के अनुसार सिलेंडरों का यह भंडारण अनधिकृत रूप से किया गया था और इनके माध्यम से कालाबाजारी किए जाने की आशंका है। कार्रवाई के दौरान दो टेम्पो चालकों को हिरासत में लेकर नारपोली पुलिस स्टेशन में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। भरारी पथक के निरीक्षक भगवान खंडेराव ने बताया कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कमिश्नर व आईजी ने परीक्षा केन्द्रो का किया निरीक्षण

ज्ञानपुर। विंध्याचल मंडल, मिर्जापुर के मंडलायुक्त राजेश प्रकाश, पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) आर.पी. सिंह, जिलाधिकारी शैलेष कुमार तथा पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने आज काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर में आयोजित उपनिरीक्षक पुलिस भर्ती परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने परीक्षा व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, अभ्यर्थियों की सुविधाओं तथा केंद्र पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा का आयोजन पूरी पारदर्शिता, शुचिता एवं निष्पक्षता के साथ कराया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने पाए। मंडलायुक्त ने कहा कि परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारी सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी तथा प्रवेश द्वारों पर सघन जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोका जा सके। पुलिस महानिरीक्षक आर.पी. सिंह ने कहा कि परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है। केंद्र के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं तथा संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देशित किया कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ कार्य करें। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि परीक्षा को सकुशल एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सभी प्रवेश द्वारों पर कड़ी जांच की जा रही है तथा परीक्षा केंद्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, परीक्षा केंद्र के प्रभारी तथा पुलिस प्रशासन उपस्थित रहे।

भदोही में बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित

ज्ञानपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की परिषदीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य की निगरानी के लिए जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक भदोही अंशुमान द्वारा आदेश जारी किया गया है। 18 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक चलने वाले मूल्यांकन कार्य को शुचितापूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए विभूति नारायण राजकीय इंटर कॉलेज, ज्ञानपुर में जनपदीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है।

लखनऊ से वाराणसी के लिए शाम 5 बजे इंटरसिटी ट्रेन चलाने की मांग

सुरियावां। तहसील उद्योग व्यापार मंडल भदोही के अध्यक्ष शेषधर गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर लखनऊ से वाराणसी के बीच नई इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि सायंकाल 5 बजे लखनऊ रेलवे स्टेशन से एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए, जो रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, बादशाहपुर, जंघई, सुरियावां और भदोही होते हुए वाराणसी तक प्रतिदिन संचालित हो। शेषधर गुप्ता ने बताया कि दोपहर 1 बजे से रात्रि 9 बजे तक लखनऊ से रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, जंघई, सुरियावां और भदोही होते हुए वाराणसी के लिए कोई सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों की लाखों जनता की सुविधा को देखते हुए मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि लखनऊ से वाराणसी के लिए शाम 5 बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की कृपा करें, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके।

पीपरगांव में मृतक चौकीदार के घर पहुंचे हिंदुस्तान आवागम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, परिजनों को दी सांत्वना

ज्ञानपुर। कोतवाली क्षेत्र के पीपरगांव में मृतक चौकीदार के घर पहुंचकर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ललित नारायण चौधरी ने परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दोषी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग सरकार से की। प्रदेश अध्यक्ष ने पीडित परिवार को आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही सरकार से मांग की कि पीडित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान किया जाए, जिससे उन्हें इस कठिन समय में सहारा मिल सके। इस दौरान पांचलाल सरोज, हरिश्चंद्र सरोज, हीरालाल, शेर बहादुर, श्याम सुंदर सहित हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा केंद्रों का एएसपी ने किया निरीक्षण

ज्ञानपुर। उप निरीक्षक (उत्तर प्रदेश पुलिस) भर्ती परीक्षा को नकलमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर पुलिस अधीक्षक भदोही शुभम अग्रवाल ने शनिवार, 14 मार्च 2026 को जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, बालिका इंटर कॉलेज ज्ञानपुर, विभूति नारायण इंटर कॉलेज ज्ञानपुर, श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल कॉलेज, एम.ए. समद इंटर कॉलेज भदोही तथा ज्ञानदेवी बालिका इंटर कॉलेज भदोही का दौरा किया। इस दौरान एएसपी ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली तथा परीक्षार्थियों के प्रवेश व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने केंद्राधीक्षकों को परीक्षा को पूरी तरह नकलमुक्त और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए पुलिस बल को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके।

कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां में किसानों के लिए गोष्ठी का आयोजन

ज्ञानपुर। कृषि विज्ञान केंद्र बेजवां में शुक्रवार को किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र के वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. विश्वेंदु द्विवेदी ने किसानों को समसामयिक कृषि मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कृषि एवं पशुपालन के साथ उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाओं तथा पशु स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में डॉ. रेखा सिंह ने महिलाओं को किचन गार्डन लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए घर की पोषण सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं डॉ. ए.के. चतुर्वेदी ने किसानों से जायद की सब्जियों की खेती करने का आग्रह किया तथा बागवानी क्षेत्र में आ रही समस्याओं के समाधान के बारे में जानकारी दी। गोष्ठी में योगेश कुमार यादव ने पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। इसके अलावा केंद्र के अन्य विशेषज्ञ सर्वेश बरनवाल, डॉ. पी.सी. सिंह और डी.पी. सिंह ने भी अपने-अपने विषयों पर किसानों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न गांवों से आए लगभग 70 पुरुष एवं महिला किसानों ने भाग लिया। गोष्ठी का उद्देश्य किसानों को रबी फसलों की कटाई-मड़ाई के साथ जायद फसलों एवं सब्जियों के चयन के बारे में जागरूक करना था।

पूर्वमंत्री रंगनाथ मिश्र को भातृ शोक

भदोही। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री सहसेपुर गांव निवासी रंगनाथ मिश्र के बडे भाई शोभनाथ मिश्र का निधन हो जाने से क्षेत्र सहित जनपद में शोक की लहर व्याप्त है। बताया जाता है कि पूर्वमंत्री रंगनाथ मिश्र के बडे भाई डा. शोभनाथ मिश्र पूर्व में वैज्ञानिक भी रह चुके थे वह अचानक स्वास्थ्य में आई खराबी को लेकर वाराणसी उपचार के लिए गये जहां पर चिकित्सको ने उन्हे लखनऊ के लिए स्थानान्तरित कर गया जहां पर उपचार के दौरान शनिवार को उनका निधन हो गया। यह समाचार फैलते ही हर जगह जहां शोक माहौल बन गया वही उनके आवास पर पहुचकर सभी राजनैतिक संगठनो के साथ ही संवेदना व्यक्त करने वालो का तांता लगा रहा।

मिशन शक्ति फेज-5 के तहत महिलाओं को किया गया जागरूक

ज्ञानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति फेज-5 के अंतर्गत जनपद भदोही में महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में जनपद के सभी थानों की एंटी रोमियो टीम द्वारा बाजारों, कस्बों, चौराहों, स्कूल-कॉलेजों और सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर छात्राओं व महिलाओं को जागरूक किया गया। अभियान के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने वूमेन पावर लाइन 1090, यूपी-112, महिला हेल्पलाइन 181, सीएम हेल्पलाइन 1076, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 सहित अन्य आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उ'वला योजना, आयुष्मान योजना आदि के बारे में पंपलेट वितरित कर महिलाओं को जागरूक किया गया।

मड़हे में खड़ी पल्सर बाइक चोरी, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज

महराजगंज। औराई थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में अज्ञात चोरों ने मड़हे में खड़ी एक पल्सर मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार त्रिलोकपुर निवासी हौंसला ने गुरुवार की रात अपनी पल्सर मोटरसाइकिल को लॉक कर मड़हे में खड़ी कर दी थी। शुक्रवार सुबह जब वह मड़हे में पहुंचे तो मोटरसाइकिल वहां से गायब थी। काफी खोजबीन के बावजूद बाइक का कोई पता नहीं चल सका। घटना के बाद पीडित ने डायल 112 पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पीडित हौंसला के प्रार्थना पत्र के आधार पर औराई पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि औराई क्षेत्र में इन दिनों मोटरसाइकिल चोरों का गिरोह सक्रिय है, जो तहसील, बैंक और बाजारों में खड़ी मोटरसाइकिलों को आसानी से चोरी कर फरार हो जाते हैं। इससे क्षेत्र के लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।

भिवंडी में अवैध पानी कनेक्शन पर मनपा का अभियान

79 लाख का जुर्माना, वसूली मात्र 6 लाख

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका के जलापूर्ति विभाग ने शहर में अवैध पानी कनेक्शन के खिलाफ पिछले चार वर्षों में व्यापक कार्रवाई की है। इस दौरान घरों, दुकानों, होटलों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पानी चोरी के मामलों में कुल 79 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया और 73 मामले भी दर्ज किए गए। हालांकि इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद अब तक सिर्फ करीब 6.12 लाख रुपये की ही वास्तविक वसूली हो सकी है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। मनपा के जलापूर्ति विभाग के अनुसार अक्टूबर 2023 से मार्च 2026 के बीच शहर में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कई जगहों पर मुख्य जलवाहिनी में छेद कर या अनधिकृत पाइपलाइन के माध्यम से पानी चोरी किए जाने के मामले सामने आए। इसके बाद संबंधित लोगों पर दंड लगाया गया और कई मामलों में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गी।

पालिका के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 में 10 लाख 98 हजार 640 रुपये, वर्ष 2024 में 26 लाख 12 हजार 3 रुपये, वर्ष 2025 में 34 लाख 15 हजार 229 रुपये और वर्ष 2026 में अब तक 8 लाख 1 हजार 400 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस तरह चार वर्षों में कुल 79 लाख 27 हजार 272 रुपये की दंडात्मक कार्रवाई दर्ज की गई। इसके बावजूद अब तक सिर्फ 6 लाख 12 हजार 379 रुपये की ही वसूली हो पाई है। जानकारी के अनुसार यह वसूली मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर पकड़ी गई पानी चोरी के मामलों से हुई है, जबकि व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लगाए गए जुर्माने की वसूली अभी तक प्रभावी ढंग से नहीं हो सकी है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अवैध पानी कनेक्शन के मामलों में वर्ष 2023 में 14, वर्ष 2024 में 32, वर्ष 2025 में 24 और वर्ष 2026 में अब तक 3 मामले दर्ज किए गए हैं। इस तरह कुल 73 मामले पुलिस में दर्ज किए जा चुके हैं। यह कार्रवाई मनपा आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त के निर्देश पर जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता संदीप पटनावर के मार्गदर्शन में की गई। अभियान में उप अभियंता सरफराज अंसारी समेत विभाग के अन्य अभियंता और कर्मचारियों ने भाग लिया। शहर में पानी चोरी के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद जुर्माने की धीमी वसूली को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले ने मनपा के जलापूर्ति प्रबंधन को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

चतुर्थ दिवस पर महिला सुरक्षा व स्व'छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सुरियावां। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के अंतर्गत आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर के चतुर्थ दिवस शनिवार को विभिन्न सामाजिक एवं जागरूकता कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल सभी स्वयंसेवकों द्वारा दैनिक क्रियाओं के बाद महाविद्यालय परिसर स्थित मां भारती मंदिर में पूजन-अर्चन एवं प्रार्थना से हुई। इसके पश्चात स्वयंसेवकों ने योग एवं व्यायाम कर शारीरिक स्वास्थ्य का संदेश दिया। इसके बाद स्वयंसेवकों ने सुरियावां नगर पंचायत स्थित श्री महावीर तीर्थ क्षेत्र बावन बीघा तालाब पहुंचकर सभी घाटों, मंदिर परिसर तथा तीर्थ क्षेत्र में स्थापित डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा की साफ-सफाई की। स्व'छता अभियान के माध्यम से समाज को स्व'छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंदिर प्रांगण में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। दोपहर भोजन के बाद आयोजित बौद्धिक सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में सुरियावां कोतवाली के उपनिरीक्षक योगेंद्र सिंह यादव उपस्थित रहे। उन्होंने स्वयंसेवकों को महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। साथ ही 1090, 112, 181 और 1076 जैसे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और प्रशासन 24 घंटे उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। किसी भी प्रकार की छेड़ख़ानी या आपात स्थिति में तुरंत इन नंबरों पर सूचना देकर सहायता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने स्वयंसेवकों को शिक्षा के साथ-साथ आत्मरक्षा के प्रति भी जागरूक रहने की सलाह दी तथा प्रतिदिन योग और व्यायाम जैसे अभ्यासों को जीवन का हिस्सा बनाने पर बल दिया, जिससे शारीरिक क्षमता मजबूत हो और आवश्यकता पड? पर व्यक्ति अपनी रक्षा स्वयं भी कर सके। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर प्रभारी बीना सिंह, डीएलएड प्रभारी धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय, रवि चंद्र यादव, रामफल बिंद, विजय कुमार श्रीवास्तव, रामकुमार प्रजापति, संतोष कुमार उपाध्याय, अजय कुमार, कृष्ण कुमार, कार्तिक गुप्ता, आर्यन गुप्ता, शिवम, खुशी उपाध्याय, रिंकी यादव, आरती यादव सहित महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, कर्मचारी तथा स्वयंसेवक-स्वयंसेविकाएं उपस्थित रहे।

पीपरगांव में मृतक चौकीदार के परिजनों से मिले लोजपा सांसद अरुण भारती

ज्ञानपुर। थाना ज्ञानपुर क्षेत्र के ग्राम सभा पीपरगांव में मृतक चौकीदार के परिजनों से मिलने शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती पहुंचे। उन्होंने पीडित परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। बताया जाता है कि 9 मार्च 2026 की सुबह करीब 7 बजे पीपरगांव निवासी जैसलाल सरोज (55) ग्राम प्रधान के यहां हैंडपंप ठीक कराने की बात कहने गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान ग्राम प्रधान के पुत्र ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे उनकी मौत हो गई। सांसद अरुण भारती ने पीडित परिवार से मिलकर घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने क्षेत्राधिकारी (सीओ) से फोन पर वार्ता कर पीडित परिवार को एक सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तथा आवासीय पट्टा देने की मांग की। साथ ही पुलिस अधीक्षक से भी बातचीत कर मामले में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति (पासी) परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में कमला कुमारी, राजीव पासवान एडवोकेट, कमल तिवारी, विकास पांडेय, धनंजय दुबे, विकास दुबे, राहुल तिवारी, संतोष पंडित, प्रदुम्न तिवारी, अभिनव तिवारी, शिवांश मिश्रा, सूरज गुप्ता, अमित शुक्ला, दुर्गेश मिश्रा, सुनील जायसवाल, विजय पाल सरोज, नंद कुमार सोनी, महेश पांडेय, सभाशंकर दुबे, विनीत सिंह, विजय राय, गोविंद पासवान, राज नीरज सिंह, गुरु प्रसाद राणा, विशाल सिंह, आशीष पासवान, अजीत पासवान, विपिन शुक्ला, योगेश पांडेय, धीरज चतुर्वेदी, आदेश चतुर्वेदी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वृद्धाश्रम के गेट पर लटकते बिजली के तार, बुजुर्गों की सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा

गोपीगंज। कोतवाली क्षेत्र के नगर स्थित खडहट्टी मोहल्ले में संचालित वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार पर झूलते बिजली के तार बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। गेट के ऊपर और आसपास मकान की दीवारों पर मकड़ी के जाल की तरह फैले विद्युत तार किसी भी समय हादसे का कारण बन सकते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई तार काफी नीचे तक लटक रहे हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट या करंट फैलने की आशंका बनी रहती है। बरसात या तेज हवा के दौरान यह खतरा और बढ़ जाता है, जिससे आश्रम में रह रहे बुजुर्गों और आसपास के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों और क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी कई बार संबंधित विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। बताया जाता है कि यह वृद्धजन आवास समाज कल्याण विभाग से वित्तपोषित है और यहां अधिकारियों का समय-समय पर आना-जाना भी रहता है। इसके बावजूद मुख्य द्वार पर फैले और झूलते तारों की समस्या अब तक जस की तस बनी हुई है। वहीं जिस गली में वृद्धाश्रम संचालित है वह काफी संकरी है, जिससे लोगों और अधिकारियों का अंदर तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और विद्युत विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द इन लटकते तारों को दुरुस्त कराया जाए, ताकि किसी संभावित हादसे से बचाव हो सके और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इंसुलेटेड केबिल लगाने की मांग, मंडल अध्यक्ष ने प्रभारी मंत्री को सौंपा पत्र

गोपीगंज। भदोही जनपद के प्रभारी मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के ऊर्जा व नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा के ज्ञानपुर स्थित राजस्व अतिथि गृह पहुंचने पर भाजपा गोपीगंज के मंडल अध्यक्ष अश्वनी अग्रवाल ने नगर की कई गलियों में इंसुलेटेड केबिल लगाने की मांग को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। मंडल अध्यक्ष अश्वनी अग्रवाल ने अपने पत्र में बताया कि गोपीगंज नगर के जिले के एकमात्र वृद्धजन आश्रम वाली गली, उदासीन अखाड़ा गली, अंजही मोहल्ला की रामनाथ गली, पश्चिम मोहल्ला के पीछे वाली गली, पुरानी ट्यूबवेल गली, मिर्जापुर रोड से माधोरामपुर गली तथा कोइरान मोहल्ला की गलियों में बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। इन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली विभाग द्वारा इंसुलेटेड केबिल न लगाए जाने के कारण लोग निजी तारों के माध्यम से बिजली का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन निजी तारों के बंडल 6 से 7 फीट की ऊंचाई पर ही लटक रहे हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त-मंडलायुक्त

ज्ञानपुर। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विंध्याचल मंडलायुक्त एवं रोल ऑब्जर्वर राजेश प्रकाश तथा जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भदोही और औराई से संबंधित फार्म-07 की कार्यवाही की गहन समीक्षा की। इस दौरान प्राप्त फार्मों की जांच के साथ उनके स्थलीय सत्यापन की स्थिति का भी अवलोकन किया गया। बैठक में संबंधित बीएलओ, सुपरवाइजर और ईआरओ मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पर्याप्त जांच के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से प्राप्त सभी फार्मों की गंभीरता से जांच की जाए और नाम अपमार्जन से पहले संबंधित स्थल का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी करने से पहले कम से कम दो गवाहों के बयान लिए जाएं, ताकि किसी पात्र मतदाता के अधिकारों का हनन न हो। मंडलायुक्त ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को निर्देशित किया कि वे स्वयं क्षेत्र में जाकर फार्मों की जांच कराएं और प्राप्त दावे व आपत्तियों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त ने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध और पारदर्शी होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, उप जिलाधिकारी औराई श्याममणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी भदोही अरुण गिरि, सहायक निर्वाचन अधिकारी संजय श्रीवास्तव सहित बीएलओ, सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मृत किसान के केसीसी खाते में 47,200 का लेन-देन, बेटे की शिकायत पर जांच शुरू

कटरा। कोइरौना थाना क्षेत्र के कटरा बाजार स्थित काशी गोमती ग्रामीण बैंक शाखा में एक मृत किसान के केसीसी खाते से 47,200 के लेन-देन का मामला सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। मामले में मृतक के बेटे की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कुड़ी खुर्द गांव निवासी चिंतामणि तिवारी की मृत्यु के बाद उनके किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण खाते में 26 फरवरी को 47,200 पहले जमा किए गए और बाद में उतनी ही राशि की निकासी दर्ज हो गई। इस लेन-देन की जानकारी मृतक के पुत्र विकाश तिवारी को मोबाइल पर आए बैंक मैसेज से हुई। विकाश तिवारी का आरोप है कि जब वह बैंक शाखा पहुंचकर खाते के लेन-देन की जानकारी लेने गए तो बैंक कर्मचारियों ने स्पष्ट जानकारी देने के बजाय टालमटोल किया। उनका यह भी कहना है कि खाते का स्टेटमेंट भी उपलब्ध नहीं कराया गया। विकाश तिवारी के अनुसार बैंक मैनेजर ने बताया कि उनके पिता के नाम पर करीब 0 हजार का ऋण था, जो ब्याज सहित बढ़कर 47,200 हो गया है और उसी का नवीनीकरण कर दिया गया है। मामले को लेकर विकाश तिवारी ने 2 मार्च को कटरा पुलिस चौकी, 7 मार्च को कोइरौना थाना, 10 मार्च को बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भदोही तथा चौथी शिकायत पुलिस अधीक्षक भदोही से की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने मामले की जांच क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर प्रभात राय को सौंप दी है। वहीं इस संबंध में बैंक शाखा प्रबंधक का कहना है कि दो खाताधारकों के नाम एक जैसे होने के कारण गलती से रकम शिकायतकर्ता के पिता के खाते में जमा हो गई थी, जिसे बाद में निकालकर सही खाते में समायोजित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

मनोरंजन

अक्षय ओबेरॉय ने देहरादून में शुरू की रोमांटिक कोर्टरूम थ्रिलर 'लव लॉटरी' की शूटिंग!

मुंबई। अभिनेता अक्षय ओबेरॉय ने अपनी आने वाली रोमांटिक कोर्टरूम थ्रिलर 'लव लॉटरी' की शूटिंग उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून में शुरू कर दी है। फिल्म लव लॉटरी का निर्देशन अरविंद पांडे कर रहे हैं और इसे कुलदीप भार्गव 'तुषार' अपनी प्रोडक्शन कंपनी सिनेमा गंज फिल्म्स.के बैनर तले बना रहे हैं। अक्षय ने हाल ही में सेट से कुछ झलकियां भी साझा की हैं, जिससे फैंस को शूटिंग के शुरुआती दिनों और खूबसूरत लोकेशन

की झलक देखने को मिली।

लव लॉटरी कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें रोमांस और सस्पेंस का मिश्रण देखने को मिलेगा। इस फिल्म में अक्षय ओबेरॉय के साथ हेली दरूवाला भी नज़र आएंगी। इसके अलावा फिल्म में कबीर दुहान सिंह और विज्यंत कोहली जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।अक्षय ओबेरॉय ने देहरादून में शूटिंग शुरू करने के अनुभव के बारे में बात करते कहा कि यह उनके लिए काफी ताज़गी भरा और उत्साहजनक अनुभव रहा है।

उन्होंने कहा, 'देहरादून में लव लॉटरी की शूटिंग शुरू करना बहुत अच्छा अनुभव रहा है। इस शहर का माहौल बेहद शांत और खूबसूरत है, और यहां से इस सफर की शुरुआत करना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने शूटिंग शुरू ही की है, लेकिन सेट पर सभी की ऊर्जा कमाल की है। अरविंद पांडे और इतनी प्रतिभाशाली टीम के साथ काम करने को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ और बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि दर्शक देखें कि हम क्या बना रहे हैं।'

बच्चों का दम घुट रहा है; मुंबई में बढ़ते प्रदूषण से दीपिका पादुकोण की चिंता बढ़ी, बीएमसी से की अपील

मुंबई। दीपिका ऑन मुंबई की एयर क्वालिटी : बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण इस समय किसी न किसी वजह से चर्चा में हैं। पहले दीपिका ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, फिर उसे समय देने के लिए उन्होंने आठ घंटे की शिफ्ट की मांग की और इसी मांग की वजह से दीपिका को ट्रोल किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें कई फिल्मों से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। हालांकि, दीपिका अपने मुद्दे से पीछे नहीं हटी हैं। मुद्दा कोई भी हो, दीपिका हमेशा उस पर अपनी साफ और मजबूत राय रखती हैं। ऐसे में दीपिका की इंस्टा स्टोरी इस समय चर्चा में है। दीपिका पादुकोण ने मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए एक पोस्ट किया है। एक्ट्रेस का कहना है कि मुंबई में खराब होती एयर क्वालिटी की वजह से शहर के लोगों और बच्चों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है।

दीपिका की इंस्टा स्टोरी

दीपिका पादुकोण ने आज अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने मुंबई में प्रदूषण की समस्या की ओर ध्यान दिलाया।

साथ ही उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से इस मामले में दखल देने और सही कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट की है। इस बीच गुरुवार को देखा गया कि मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार चला गया है। यह AQI सेहत के लिए नुकसानदायक है।

दीपिका ने मुंबई में प्रदूषण के स्तर का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इस फोटो के साथ उन्होंने शहर के नगर निगम यानी बीएमसी को टैग किया है और अधिकारियों से मामले की जांच करने की रिक्वेस्ट की है। शहर की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए एक्ट्रेस ने लिखा कि मुंबई में रहने वाले लोग, खासकर बच्चे, खराब होती एयर क्वालिटी के कारण दम घुटने जैसी स्थिति महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही दीपिका ने यह सवाल भी उठाया है, 'यह कैसे सही हो सकता है?'

दीपिका पादुकोण से पहले एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा और सैयामी खेर ने भी मुंबई में खराब होती एयर क्वालिटी पर चिंता जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका शाहरुख खान की आने वाली फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी। फिल्म में सुहाना खान समेत कई बड़े एक्टर्स हैं। इसमें अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, जयदीप अहलावत और रानी मुखर्जी शामिल हैं। इसके अलावा वह एटली की एक तेलुगु एक्शन फिल्म का भी हिस्सा हैं, इस प्रोजेक्ट में वह अल्लू अर्जुन के साथ लीड रोल में नजर आएंगी।

विश्वकप ट्रॉफी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे कप्तान सूर्यकुमार और कोच गंभीर, बप्पा का लिया आशीर्वाद

मुंबई। न्यूजीलैंड को हराकर टीम इंडिया ने हाल ही में लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने कीवियों को 96 रनों से हराया था और खिताब अपने नाम किया। शनिवार को आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी के साथ मुंबई स्थित सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और दर्शन किए।

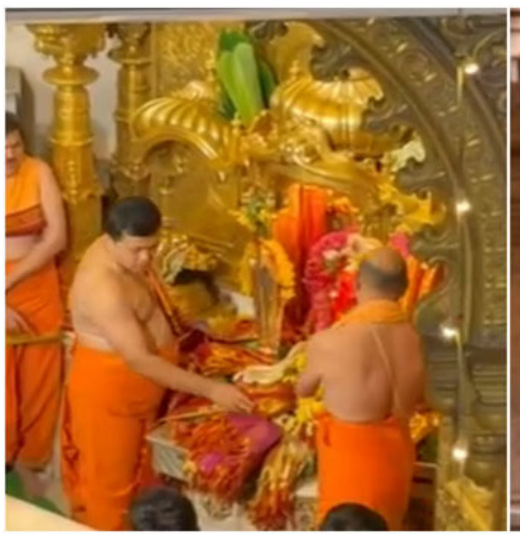

भारत ने तीसरी बार जीता था खिताब

भारतीय टीम ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में रिकॉर्ड तीसरी बार टी20 विश्व कप को अपने नाम किया था। इसके साथ ही भारत घरेलू सरजमीं पर टी20 विश्व कप का खिताब जीतने वाला पहला देश भी बना। भारतीय टीम टी20 विश्व कप के खिताब का बचाव करने वाली भी दुनिया की पहली टीम बनी थी।

सूर्यकुमार के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पांच साल पूरे

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पांच साल पूरे कर लिए हैं। सूर्यकुमार ने 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू किया था। भारत ने हाल ही में सूर्यकुमार की कप्तानी में टी20 विश्व कप का खिताब जीता था। सूर्यकुमार ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और अपनी यात्रा के पल को साझा किया है।

मैदान पर ग्लव्स-हेलमेट फेंकना सलमान आगा को पड़ा भारी, आईसीसी ने लगाई फटकार

नई दिल्ली। पाकिस्तान की टीम इन दिनों बांग्लादेश दौरे पर है और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। शुक्रवार को मीरपुर में खेले गए दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान आगा रनआउट होने के बाद नाराज हो गए थे और उन्होंने हेलमेट और ग्लव्स मैदान पर फेंक दिए थे। अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

परिषद (आईसीसी) ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर आगा को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई है।

आईसीसी ने क्या कहा?

आईसीसी ने बताया कि आगा ने खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए निर्धारित आईसीसी की आचार संहिता के लेवल-1 नियम का उल्लंघन किया है। यह मामला अनुच्छेद 2.2 से जुड़ा है, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण, कपड़ों या मैदान की वस्तुओं के दुरुपयोग से संबंधित है।

क्या विश्वकप से बाहर होने के बाद लगेगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना? पीसीबी अधिकारी ने कर दिया साफ

नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में संपन्न हुए टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम सुपर-8 चरण से ही बाहर हो गई। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) खिलाड़ियों पर जुर्माना लगा सकता है। हालांकि, अब पीसीबी के प्रवक्ता आमिर मीर ने साफ किया है बोर्ड ने अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।

सुपर-8 चरण में समाप्त हो गया था सफर

पाकिस्तान की टीम हाल ही में समाप्त हुए टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही थी। टीम सुपर-8 चरण से ही बाहर हो गई थी। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पीसीबी खिलाड़ियों पर जुर्माना लगा सकता है। हालांकि, अब पीसीबी प्रवक्ता ने इन दावों को खारिज करते हुए साफ कहा कि बोर्ड ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।

क्या बोले पीसीबी प्रवक्ता?

आमिर मीर ने कहा, 'किसी भी खिलाड़ी पर जुर्माना नहीं लगाया गया है। लेकिन हां, बोर्ड खिलाड़ियों के लिए एक नई रणनीति तैयार करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें काफी प्रोत्साहन मिलता है।' मीर ने बताया कि अब हर खिलाड़ी लगभग 6-7 करोड़ पाकिस्तानी रुपये कमाता है, इसलिए बोर्ड उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें जवाबदेह बनाने पर विचार कर रहा है।

पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन

पाकिस्तान टीम को सुपर-8 में इंग्लैंड के हाथों हार मिली। इससे पहले टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर-8 मैच बारिश से धुल गया था। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले थे। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को या तो 64 रन से या फिर 13.1 ओवर में जीत हासिल करनी थी। उस मैच में पाकिस्तान टीम ने 212 रन बनाए, लेकिन जवाब में श्रीलंका ने भी 207 रन बना डाले और बेहतर नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। इस तरह पाकिस्तान की टीम 2023 वनडे विश्वकप, 2024 टी20 विश्वकप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में पहुंचने में नाकाम रही।

कुलदीप की शादी में सितारों का जमावड़ा, रिंकू और रैना के साथ नजर आए फील्डिंग कोच दिलीप

मसूरी। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव आज नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मसूरी में वह बचपन की दोस्त वंशिका के साथ शादी रचाएंगे। इस समारोह में शामिल होने के लिए पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, युजवेंद्र चहल सहित कई हस्तियां पहुंची हैं।

शादी के लिए तैयारियों जोर-शोर से जारी

कुलदीप और वंशिका की शादी के प्री वेडिंग कार्यक्रम फिलहाल जारी हैं। शुक्रवार को मेहंदी और संगीत सेरेमनी थी जिसमें कुलदीप जमकर थिरके थे। शादी समारोह के लिए होटल को फूलों, रोशनी और पारंपरिक सजावट से विशेष रूप से सजाया गया है। होटल प्रबंधन ने मेहमानों के स्वागत और आतिथ्य के लिए बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं की हैं।

मेहमानों के लिए पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ उत्तराखंडी खाने का भी खास इंतजाम किया गया है। शादी में भारतीय क्रिकेट टीम के कई बड़े खिलाड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है, इसलिए आयोजन स्थल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। होटल परिसर में केवल आमंत्रित मेहमानों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन और होटल प्रबंधन ने कार्यक्रम को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है।

संगीत सेरेमनी में रैना-चहल आए नजर

इससे पहले शुक्रवार को कुलदीप और वंशिका की मेहंदी और संगीत सेरेमनी हुई। संगीत सेरेमनी में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, युजवेंद्र चहल थिरकते हुए नजर आए। रैना ने कुलदीप यादव के साथ भी डांस किया।

भारतीय टीम के फील्डिंग कोच टी. दिलीप भी संगीत सेरेमनी में उपस्थित रहे। वहीं, टी20 विश्व कप टीम का हिस्सा रहे रिंकू सिंह भी अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ कुलदीप की शादी में शिरकत करने मसूरी पहुंच गए हैं।

कब होगा रिसेप्शन?

लखनऊ में 17 मार्च को कुलदीप यादव और वंशिका का रिसेप्शन रखा गया है। बता दें कि कुलदीप औप वंशिका दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वंशिका ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से पढ़ाई की है।

पीएसएल को नजरअंदाज करने पर बौखलाया पाकिस्तान, मुजरबानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में पीसीबी

कराची। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने आईपीएल को तवज्जो देते हुए पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में खेलने से इनकार कर दिया था। अब पाकिस्तान मुजरबानी के इस फैसले से बौखला गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दरअसल, कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने मुजरबानी को अपनी टीम में शामिल किया था, जिसके बाद जिम्बाब्वे के इस तेज गेंदबाज ने पीएसएल की फ्रेंचाइजी इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी अनुपलब्धता के बारे में सूचित कर दिया था।

इस्लामाबाद युनाइटेड ने मुजरबानी से किया था करार

मुजरबानी इससे पहले पीएसएल में मुल्तान सुल्तान को खिताब दिला चुके हैं। उन्हें 11 फरवरी को पीएसएल की नीलामी में किसी ने नहीं खरीदा था, लेकिन बाद में इस्लामाबाद फ्रेंचाइजी ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार

जोसेफ की जगह मुजरबानी के साथ करार किया था। हालांकि, केकेआर के साथ करार करने के बाद मुजरबानी ने आईपीएल में ही खेलने का फैसला किया।

पाकिस्तान को रास नहीं आया फैसला

मुजरबानी का यह फैसला पाकिस्तान को जरा भी रास नहीं आया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, पीसीबी मुजरबानी के फैसले को करार के उल्लंघन के रूप में देख रही है और कानूनी कार्रवाई के लिए विकल्पों पर विचार कर रही है। यह लगातार दूसरा साल है जब किसी खिलाड़ी ने पीएसएल करार पहले से होने के बावजूद आईपीएल को प्राथमिकता दी है। पिछले सीजन दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने भी ऐसा ही कदम उठाया था। उन्हें पेशावर जाल्मी ने चुना था। बाद में वह आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस से जुड़ गए थे।

मुजरबानी ने किया था प्रभावित

ब्लेसिंग मुजरबानी ने हाल में संपन्न टी20 विश्व कप 2026 में शानदार गेंदबाजी की थी और जिम्बाब्वे को सुपर-8 में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मुजरबानी ने 13 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुजरबानी के चार विकेट ने ही जिम्बाब्वे को ग्रुप स्टेज में जीत दिलाई थी। आईपीएल और पीएसएल का सत्र एक बार फिर टकरा रहा है। आईपीएल 28 मार्च से शुरू हो रहा है, जबकि पीएसएल 26 मार्च से तीन मई तक प्रस्तावित है।

क्या आखिरी बार चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में दिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी? इरफान पठान का बड़ा बयान

नई दिल्ली। महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल में भविष्य को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना है कि आईपीएल के आगामी सत्र में प्रशंसकों को शायद आखिरी बार धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में खेलते देखने का मौका मिले।

आखिरी बार आईपीएल में दिखेंगे धोनी?

आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले धोनी के संन्यास को लेकर अटकलें फिर से बढ़ गई हैं। खासकर तब, जब सीएसके ने संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड कर अपनी टीम में शामिल किया। कई लोगों का मानना है कि इस कदम से धोनी मैदान पर कम भूमिका निभाते हुए टीम के मेंटर के रूप में ज्यादा योगदान दे सकते हैं।

इरफान पठान ने क्या कहा?

जियोहॉटस्टार के शो 'गेम प्लान' में इरफान पठान ने कहा, 'सीएसके बिना धोनी के अधूरी है। यह सीजन शायद आखिरी बार हो सकता है जब हम उन्हें पीली जर्सी में खेलते देखें। सीएसके और आईपीएल को उनके बिना सोच पाना मुश्किल है।'

उन्होंने यह भी कहा कि हर साल आईपीएल आते ही धोनी पूरी तैयारी के साथ नजर आते हैं और इस बार भी वह काफी फिट दिख रहे हैं।

टीम में मेंटर की भूमिका निभा सकते हैं धोनी

44 वर्षीय धोनी इस महीने की शुरुआत में ही चेन्नई में टीम कैंप से जुड़ चुके हैं और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई वाली टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। पठान के मुताबिक इस सीजन में धोनी की भूमिका युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने की हो सकती है। उन्होंने कहा कि टीम में नेतृत्व समूह तैयार किया जा रहा है, जिसमें संजू सैमसन के साथ-साथ अन्य खिलाड़ी भी शामिल होंगे।

युवाओं को जिम्मेदारी लेने का समय

पठान का मानना है कि अब टीम में युवा खिलाड़ियों को आगे आकर जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों को भविष्य की कमान संभालने के लिए तैयार किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे

संशोधन सूचना

टेंडर संख्या W641-22-23-06C (E-434312) के संदर्भ में निविदा बंद होने की तिथि और समय को 17.03.2026 प्रातः 11:00 बजे के स्थान पर अब 31.03.2026 प्रातः 11:00 बजे पढ़ा जाए। अन्य सभी नियम और शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। 1217

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल

संख्या W/623/5/1/NIT दिनांक: 12.03.2026

ई-टेंडरिंग नोटिस

मंडल रेल प्रबंधक / मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा) पश्चिम रेलवे रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिये "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते है । विवरण इस प्रकार है- **क्र.सं.: 1. ई-टेंडरिंग संख्या: RTM-2025-26-194. कार्य का नाम:** Sehore - Providing officer rest house having 05 suits in connection simhastha 2028 including with Electrical Work. **अनुमानित लागत:** रु 1,11,98,294.94. **बयाना राशि:** रु 2,06,000/-. **कार्य समापन अवधि:** 10 माह। **क्र.सं.: 2. ई-टेंडरिंग संख्या: RTM-2025-26-200. कार्य का नाम:** Maksi - Bhopal Section - Raising of platforms at Panchawan at Platform No.1, Parbati at Platform No.1 and 04 meter wide Foot Over Bridge with 02 ramp landings at Panchawan and Parbati station. **अनुमानित लागत:** रु 8,61,60,389.72. **बयाना राशि:** रु 5,80,900/-. **कार्य समापन अवधि:** 15 माह। **वेबसाईट पर अपलोड करने की तिथि दोनों टेंडर के लिए:** 12.03.2026. **निविदा खुलने की तिथि दोनों टेंडर के लिए:** 09.04.2026. विस्तृत निविदा सूचना अर्हता शर्तें एवं अन्य शर्तें वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। निविदा फार्म की लागत शून्य है। DE/5/1/510

हमें लाईक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

विभिन्न कार्य

पश्चिम रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर (WA), 6वीं मंजिल, इंजीनियरिंग विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई - 400008 द्वारा निम्नलिखित ई-टेंडर आमंत्रित किए गए हैं: **क्रमांक** : 1 **ई-टेंडर सूचना संख्या** : BCT/25-26/336, दिनांक 09.03.2026 **कार्य व स्थान** : विरार - जोरावासन खंड में एडीईएन/दहाणू रोड के अधिकार क्षेत्र में पालघर, उमरगांव और बोइसर में प्रत्येक स्थान पर 50 केएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का प्रावधान। **कार्य की अनुमानित लागत** : 4,42,54,042.27 रुपये **बयाना राशि** : 3,71,300 रुपये। **क्रमांक** : **2 ई-टेंडर सूचना संख्या** : BCT/25-26/337, दिनांक 09.03.2026 **कार्य व स्थान** : **विरार - जोरावासन खंड में** वलसाड में 25 मीटर का 01 पिट लाइन तथा 30 मीटर × 9 मीटर × 15 मीटर आकार का 01 टॉवर वैगन शेड का प्रावधान। **कार्य की अनुमानित लागत** : 93,52,977.26 रुपये। **बयाना राशि** : 1,87,100 रुपये। **दोनों टेंडरों के लिए निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय** :07.04.2026, अपराह्न 15:00 बजे तक। **निविदा खोलने की तिथि व समय** : 07.04.2026, अपराह्न 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट देखें: www.ireps.gov.in 1209

हमें फॉलो करें facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद मंडल

विभिन्न इंजीनियरिंग काम

ई-निविदा सूचना संख्या 28 वर्ष 2025-26 दिनांक : 13.03.2026

सं	ई-निविदा संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	EMD राशि
1	DRM-ADI-214-2025-26	साबरमती – मंडल रेल चिकित्सालय, साबरमती का विस्तार करते हुए नया बाल चिकित्सा (पीडियाट्रिक) वार्ड, नर्सिंग स्टेशन तथा MDDTI-SBI में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) केंद्र की व्यवस्था सहित सहायक कार्य, मंडल अभियंता (वर्क्स) अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में। (संयुक्त निविदा)	2,21,24,412.55	2,60,600.00
2	DRM-ADI-215-2025-26	पालनपुर–सामख्याली सेक्शन के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 127 किमी 145/1-2, 138 किमी 158/8-9 एवं 139 किमी 160/3-4 को रोड अंडर ब्रिज बनाकर समाप्त करना, Sr. DEN (NW) – अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में।	33,09,01,809.76	18,04,500.00

ई-निविदा बंद होने की तिथि: दिनांक 07/04/2026 समय 15:00 बजे **कार्यालय का पता:** वरि. मंडल इंजीनियर (सम.)-अहमदाबाद, डी. आर.एम. ऑफिस, चामुंडा ब्रिज के पास, नई स्वदेशी मिल के सामने, नरोडा रोड, अमदुपुरा, अहमदाबाद- 382345 **ई-निविदा में भाग लेने हेतु वेबसाइट: www.ireps.gov.in** ADI 309

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

प. एशिया संकट के बावजूद उर्वरकों भारत में उर्वरकों की कमी नहीं, खरीफ सीजन से पहले किसानों को राहत

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में बाधाओं के बावजूद भारत में 2026 के खरीफ बुवाई सीजन से पहले उर्वरकों का पर्याप्त भंडार मौजूद है। यूरिया, डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और एनपीके जैसे प्रमुख पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

यूरिया, डीएपी और एनपीके का मजबूत भंडार

सूत्रों के अनुसार, इस समय यूरिया का भंडार लगभग 62 लाख टन है, जो पिछले साल इसी अवधि के मुकाबले करीब 10 लाख टन अधिक है। डीएपी का भंडार करीब 25 लाख टन आंका गया है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुना है। जबकि एनपीके का भंडार रिकॉर्ड 56 लाख टन तक पहुंच गया है। पिछले साल इसी समय यह 31 लाख टन था। आने वाले महीनों में घरेलू उत्पादन भी उर्वरकों की उपलब्धता को मजबूत करेगा।

तेज कर दी गई यूरिया आयात की प्रक्रिया

आम तौर पर यूरिया का उत्पादन अनुमानित लगभग 25 लाख टन प्रति

माह रहता है। हालांकि, मार्च में उत्पादन लगभग 17 लाख टन रहने की संभावना है, क्योंकि कुछ संयंत्रों ने गैस के बेहतर उपयोग के लिए पहले ही रखरखाव का काम शुरू कर दिया है। सरकार ने आयात की प्रक्रिया भी तेज कर दी है।

यूरिया के लिए जारी किया था वैश्विक टेंडर

सूत्रों ने बताया कि इस साल की शुरुआत में यूरिया के लिए वैश्विक निविदा (टेंडर) पहले ही जारी कर दी गई थी और फरवरी के मध्य में लगभग 13.5 लाख टन यूरिया का ऑर्डर दिया गया। आयातित यूरिया का लगभग 90 फीसदी मार्च के अंत तक भारत पहुंचने की उम्मीद है।

ईपीएमसी के जरिये गैस खरीद को मंजूरी

सरकार ने सशक्त पूल प्रबंधन समिति (ईपीएमसी) के जरिये तुरंत गैस खरीद को भी मंजूरी दी है। माना जा रहा है कि गेल जल्द ही खरीद का पहला चरण शुरू करेगा। रूस से उर्वरकों की आपूर्ति बिना बाधा के जारी है, जबकि रूस और मोरक्को से आने वाली आपूर्ति फिलहाल पारंपरिक समुद्री मार्गों में बाधा के कारण केप ऑफ गुड होप के रास्ते भेजी जा रही है। सऊदी अरब के साथ भारत का डीएपी के लिए पांच साल का आपूर्ति समझौता भी जारी है, जिससे इस अहम उर्वरक का आयात लगातार होता रहेगा।

खरीफ से पहले स्थिति

अधिकारियों ने कहा कि आम तौर पर मई के मध्य से शुरू होने वाले खरीफ सीजन से पहले उर्वरकों का भंडार पर्याप्त रहने की उम्मीद है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति का पूरा अनुमान मानसून की प्रगति और समय पर भी निर्भर करेगा। अधिकारियों ने बताया कि 652 जिलों में उर्वरकों की बिक्री पर एक डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम के जरिये नजर रखी जा रही है, ताकि असामान्य बिक्री के तर्ज का पता लगाया जा सके और जमाखोरी या गड़बड़ी को रोका जा सके।

गैस की बढ़ती मांग के बीच सरकार का बड़ा फैसलाः इन लोगों को सरकार नहीं देगा एलपीजी, दोहरे कनेक्शन पर सख्ती

नई दिल्ली। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की सप्लाई को लेकर बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब जिन घरों में पहले से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन मौजूद है, उन्हें घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

इन लोगों को नहीं मिलेगी एलपीजी

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, यदि किसी उपभोक्ता के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, तो उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। यह फैसला शनिवार को जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार पीएनजी कनेक्शन रखने वाला कोई भी व्यक्ति नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं ले सकेगा। पीएनजी और एलपीजी दोनों रखने वाले उपभोक्ता एलपीजी सिलेंडर का रिफिल नहीं प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा। सरकारी तेल कंपनियां (आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल) और उनके वितरक ऐसे घरों में एलपीजी प्रदान नहीं कर सकेंगे।

'एक घर-एक ईंधन' नीति लागू

सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि एलपीजी की सीमित आपूर्ति को बेहतर तरीके से प्रबंधित हो और उन जरूरतमंद परिवारों तक सिलेंडर पहुंचे, जिनके पास पीएनजी जैसा विकल्प नहीं है। पीएनजी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है, जहां पाइपलाइन के माध्यम से सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल गैस मिलती है। वहीं ग्रामीण और छोटे शहरों में अभी भी एलपीजी ही मुख्य ईंधन है। इस बदलाव से पीएनजी वाले क्षेत्रों में एलपीजी की मांग कम होगी, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी वाले सिलेंडर की उपलब्धता बढ़ेगी।

यह कदम 'एक घर-एक ईंधन' नीति की दिशा में भी माना जा रहा है। पहले भी सरकार ने दोहरे कनेक्शन पर रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब यह नियम स्पष्ट और सख्त रूप से लागू किया गया है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि यदि उनके पास दोनों कनेक्शन हैं, तो वे तुरंत नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी के पोर्टल पर जाकर कनेक्शन सरेंडर करें। सरेंडर करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

शशि थरूर की सरकार से अपील- ईरान युद्ध खत्म कराने के लिए कूटनीतिक पहल करे भारत, बढ़ रहा एलपीजी संकट

तिरुवनंतपुरम। अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच जारी युद्ध पर शनिवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य तभी खुल सकता है जब युद्ध खत्म होगा, क्योंकि ईरान के पास दुनिया पर दबाव बनाने के बहुत कम तरीके हैं। उन्होंने कहा कि इस समय ईरान कमजोर स्थिति में है।

'ईरान हमलों का ज्यादा शिकार'

थरूर ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और करीब पांच हजार ईरानी भी मारे गए हैं। संघर्ष का संतुलन पूरी तरह ईरान के खिलाफ रहा है। ईरान में ज्यादा तबाही मची है और उस पर ज्यादा मिसाइल हमले हुए हैं, जबकि ईरानी ड्रोन और मिसाइलों से अन्य जगहों पर कम हमले हुए हैं। इसलिए ईरान फिलहाल हमलों का ज्यादा शिकार हो रहा है।

'दुनिया के लिए चीजें मुश्किल बना सकता है ईरान'

उन्होंने आगे कहा, ऐसी स्थिति में ईरान दुनिया के लिए तेल आपूर्ति, जहाजों की आवाजाही और हवाई मार्ग को सीमित करके चीजों को मुश्किल और महंगा बना सकता है। यही उसका दबाव बनाने का तरीका है। उन्होंने कहा, जब तक युद्ध लड़ रहे पक्षों को इसे जल्दी खत्म करने के लिए राजी नहीं किया जाता, तब तक ईरान यह दबाव छोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यह युद्ध जल्दी खत्म हो, ताकि न केवल हमारी अर्थव्यवस्था बल्कि पूरे क्षेत्र को बचाया जा सके।

सरकार से समाधान के लिए पहल करने की अपील

कांग्रेस नेता ने कहा, इस समस्या का बहुत जल्दी समाधान होना चाहिए। थरूर ने कहा कि उन्होंने पहले ही सार्वजनिक रूप से भारत सरकार से अपील की है कि वह संघर्ष खत्म कराने, तनाव कम करने और कूटनीति के जरिये समाधान के लिए पहल करे। उन्होंने कहा, तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और गैस की भी समस्या है। असली दिक्कत यह है कि गैस की कमी हो रही है, क्योंकि कतर से गैस बाहर नहीं जा पा रही है, जबकि कतर उस क्षेत्र से भारत के आयात की जाने वाली गैस का लगभग 40 फीसदी देता है।

'होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने पैदा हुई एलपीजी की समस्या'

उन्होंने कहा, होर्मुज जलडमरूमध्य एक संकरा समुद्री मार्ग है, जिसे ईरान ने लगभग बंद कर दिया है। पिछले कई दिनों में केवल तीन या चार जहाज ही इस मार्ग से गुजर पाए हैं, जो बहुत कम है। यह जहाजों की आवाजाही के लिए एक बहुत बड़ा और अहम मार्ग है। इसके कारण एलपीजी की समस्या पैदा हो गई है।

'रसोईघर और रेस्तरां उद्योग पर पड़ रहा असर'

उन्होंने कहा कि यह स्थिति अब आम लोगों के लिए संकट बनती जा रही है। थरूर ने कहा कि सरकार का यह कहना सही हो सकता है कि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी चीजों की कोई खास कमी नहीं है।

उत्तर कोरिया ने दागे 10 अज्ञात मिसाइल, जापान और दक्षिण कोरिया में हड़कंप, अब एशिया में मंडराया युद्ध का खतरा!

प्योंगयांग। एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक बार फिर सैन्य तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया ने आज पूर्व दिशा की ओर कई अज्ञात मिसाइल दागे, जिससे दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका सहित पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गयी हैं। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय और संयुक्त सेनाध्यक्षों ने पुष्टि की है कि उत्तर कोरिया ने राजधानी क्षेत्र के सुनान इलाके से लगभग दस अज्ञात मिसाइल पूर्वी सागर की ओर छोड़े। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं तथा क्षेत्र में कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गयी है।

दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार यह मिसाइल लगभग दोपहर एक बजकर बीस मिनट के आसपास छोड़े गये। प्रारंभिक आकलन के अनुसार इनमें से कम से कम एक मिसाइल संभवतः दूरमार्ग मिसाइल की श्रेणी का था। जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उत्तरी कोरिया से छोड़ा गया यह मिसाइल संभवतः समुद्र में गिर चुका है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरा है, जिससे किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। जापान की सरकार ने इस घटना के बाद तुरंत आपात प्रतिक्रिया तंत्र सक्रिय कर दिया। प्रधानमंत्री साने ताकाइची के कार्यालय ने सुरक्षा एजेंसियों को विमान, जहाज और अन्य सैन्य संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही संभावित आपात परिस्थितियों के लिए सभी सावधानी उपायों को लागू करने के आदेश भी जारी किये गये हैं।

उधर, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उत्तर कोरिया की ओर से इस प्रकार की गतिविधि ऐसे समय में सामने आयी है जब कुछ सप्ताह पहले ही प्योंगयांग ने सियोल की शांति पहल को छलपूर्ण और भ्रामक बताया था। हम आपको बता दें कि उत्तर कोरिया लगातार दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का विरोध करता रहा है। उसका आरोप है कि ये अभ्यास वास्तव में उसके खिलाफ सैन्य आक्रमण की तैयारी के समान हैं। हालांकि सियोल और वाशिंगटन का कहना है कि यह अभ्यास पूरी तरह रक्षात्मक प्रकृति के हैं और इनका उद्देश्य केवल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य तैयारियों की जांच करना है।

इस बीच कूटनीतिक स्तर पर भी नई अटकलें सामने आयी हैं। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री किम मिन सिओक ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ एक और शिखर वार्ता उपयोगी हो सकती है। यह बयान ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में तनाव फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है और कई देश संभावित कूटनीतिक पहल की संभावना तलाश रहे हैं।

देखा जाये तो उत्तर कोरिया की यह मिसाइल गतिविधि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण संकेत देती है। इसका निहितार्थ यह भी है कि प्योंगयांग अपनी सैन्य क्षमता और प्रतिरोधक शक्ति को लगातार प्रदर्शित करना चाहता है। इस प्रकार के मिसाइल परीक्षण उसके लिए रणनीतिक संदेश का माध्यम होते हैं, जिनसे वह अपने विरोधियों को यह बताना चाहता है कि उसके पास जवाबी क्षमता मौजूद है।

इसके अलावा, इस प्रकार की गतिविधियां अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत कर सकती हैं। क्षेत्र में बढ़ते खतरे को देखते हुए ये देश अपने संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा तंत्र को और सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र में सैन्य प्रतिस्पर्धा और बढ़ने की संभावना है। साथ ही इस घटना से कूटनीतिक वार्ता की संभावना भी प्रभावित हो सकती है। एक ओर जहां सैन्य गतिविधियां तनाव बढ़ाती हैं, वहीं दूसरी ओर वे अक्सर वार्ता के लिए दबाव बनाने का साधन भी बनती हैं। संभव है कि उत्तरी कोरिया इस तरह की कार्रवाई के माध्यम से भविष्य की वार्ताओं में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता हो।

'एयर डिफेंस हमारी रोज़ की ज़रूरत है', रूस के हमले के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील

कीव। रूस ने यूक्रेन पर 430 ड्रोन और 68 मिसाइलों से बड़ा हमला किया, जिसमें कीव के ऊर्जा ढांचे और नागरिक इमारतों को निशाना बनाया गया। इस हमले में चार लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को वायु रक्षा प्रणालियों की 'रोज़मर्रा की आवश्यकता' का प्रमाण बताते हुए सहयोगी देशों से तुरंत मदद की अपील की है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि रूस ने यूक्रेन की ओर लगभग 430 ड्रोन और कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और देश के लिए वायु रक्षा प्रणाली के महत्व को दैनिक आवश्यकता बताया। उन्होंने मिसाइल आपूर्ति समझौतों में तेजी लाने का आग्रह किया और वायु रक्षा मिसाइलों के उत्पादन को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने यह टिप्पणी एक्स पर एक पोस्ट में की और कहा कि रूस ने विभिन्न प्रकार के लगभग 430 ड्रोन और बड़ी संख्या में मिसाइलें दागीं। इनमें 13 बैलिस्टिक मिसाइलें थीं और कुल मिसाइलों की संख्या 68 थी। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार इनमें से 58 को यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली ने रोक

दिया। पोस्ट में आगे कहा गया कि ऐसे हमले हवाई रक्षा के महत्व की याद दिलाते हैं। उन्होंने लिखा, 'रूसी हमलों की हर रात हमारे सभी साझेदारों को यह याद दिलाती है कि हवाई रक्षा और उसके लिए मिसाइलें वास्तव में एक दैनिक आवश्यकता हैं। मिसाइल आपूर्ति पर हर समझौता लंबित नहीं रह सकता– इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। हवाई रक्षा मिसाइलों के उत्पादन को बढ़ाने के हमारे समझौते एक महत्वपूर्ण दिशा हैं और इस दिशा में शत-प्रतिशत ध्यान देने की आवश्यकता है।'

उन्होंने यह भी कहा कि रूस मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध का फायदा उठाकर यूरोप और यूक्रेन में और अधिक विनाश करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए खतरे के वास्तविक स्तर को समझते हुए तैयारी करना जरूरी है। उनके अनुसार यूरोप को हवाई रक्षा मिसाइलों–खासकर बैलिस्टिक खतरों से मुकाबला करने वाली मिसाइलों–और जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक अन्य प्रणालियों के उत्पादन को विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूरोप इस स्तर की विश्वसनीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है और मदद करने वाले सभी देशों को धन्यवाद दिया। ज़ेलेंस्की ने बताया कि कीव, सूमी, खार्किव, निप्रो और मायकोलाइव क्षेत्रों में हमले के बाद हालात संभालने के प्रयास जारी हैं और सभी आवश्यक सेवाएं इसमें लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि रूसी हमलावरों का मुख्य निशाना कीव क्षेत्र का ऊर्जा ढांचा था, लेकिन दुर्भाग्य से आम आवासीय इमारतों, स्कूलों और नागरिक व्यवसायों को भी सीधा नुकसान पहुंचा। अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कई लोग घायल हुए हैं और कुछ लोग अभी भी चिकित्सा सहायता ले रहे हैं।

ट्रंप के बातचीत के दावे पर ईरान का पलटवार, कहा- 5 साल तक War के लिए हैं तैयार

तेहरान। पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के साथ ही तेहरान के वार्ता की मांग करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए, ईरान के सर्वोच्च नेता के भारत में प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने शनिवार को इन दावों को नकारते हुए कहा कि तेहरान पांच साल तक भी युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है। एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में इलाही ने इस बात से स्पष्ट इनकार किया कि ईरान वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्ता करना चाहता है, और कहा कि वार्ता के बीच में ही वाशिंगटन ने तेहरान को निशाना बनाया था।

इलाही ने कहा कि नहीं। बिल्कुल नहीं। ईरान इस समय उनके साथ बातचीत नहीं करना चाहता क्योंकि उन्होंने ही यह युद्ध शुरू किया है। और हमें उनके साथ अनुभव है। दो बार जब हम उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने हम पर हमला किया। उन्होंने हमें निशाना बनाया। इलाही ने कहा कि तेहरान अपने दुश्मनों के सामने नहीं झुकेगा और जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के लिए तैयार है। ईरान और इराक के बीच संघर्ष से तुलना करते हुए प्रतिनिधि ने कहा कि

ईरान को लंबे युद्ध का अनुभव है।

उन्होंने कहा कि मुझे इस युद्ध की कोई समयसीमा नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ईरान इस युद्ध को अंत तक, यहां तक ??कि पांच साल तक भी जारी रखने के लिए तैयार है। और हमें युद्ध का अनुभव है। उस समय ईरान और इराक के बीच आठ साल के युद्ध का हमें अनुभव था। और हम तैयार हैं। और अगर आप ईरान की सड़कों पर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि सभी लोग वहां मौजूद हैं और प्रतिशोध के नारे लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि हम अपना खून देने को तैयार हैं, लेकिन अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं।

इलाही ने यह भी कहा कि ईरान ने क्षेत्र में तनाव बढ़ने से रोकने के कई प्रयास किए हैं और पड़ोसी देशों से मध्य पूर्व में संघर्ष को रोकने में मदद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते थे। हमने कई बार इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के युद्ध को टालने का प्रयास किया। हमने अपने पड़ोसियों को यह भी सूचित किया था कि उन्हें इस युद्ध क्षेत्र से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र अब और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने मौजूदा संघर्ष पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह संघर्ष न केवल ईरान के लोगों को प्रभावित कर रहा है बल्कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और व्यापक आर्थिक प्रभावों का हवाला देते हुए यह एक वैश्विक चिंता का विषय भी बन गया है।

बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला, हेलीपैड को बनाया निशाना; धुएं के गुबार से दहला परिसर – इराक का दावा

बगदाद। इस हमले के बाद बगदाद के 'ग्रीन ज़ोन' की सुरक्षा और अधिक सख्त कर दी गई है। इराक में तैनात अमेरिकी सैन्य बल और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। इस हमले को पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे सीधे संघर्ष की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।

इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास परिसर के भीतर एक हेलीपैड पर मिसाइल से हमला हुआ। इराक के दो सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एसोसिएटेड प्रेस के पास मौजूद फुटेज में शनिवार सुबह दूतावास परिसर के ऊपर धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। दुनिया में अमेरिका के सबसे बड़े राजनयिक केंद्रों में शामिल यह विशाल दूतावास परिसर पहले भी ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा दागे गए रॉकेट और ड्रोन का कई बार निशाना बन चुका है।

बगदाद का 'ग्रीन ज़ोन' दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक माना जाता है, जहाँ कई देशों के दूतावास और सरकारी कार्यालय स्थित हैं। इस उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में मिसाइल का सीधे दूतावास के हेलीपैड पर गिरना सुरक्षा घेरे में एक बड़ी चूक माना जा रहा है। विशेष बात यह है कि दूतावास के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो अक्सर ऐसे रॉकेटों को हवा में ही नष्ट कर देता है, लेकिन इस बार मिसाइल परिसर के अंदर गिरने में सफल रही।

ईरान समर्थित समूहों पर शक

यह विशाल दूतावास परिसर पहले भी कई बार ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों द्वारा रॉकेट और ड्रोन हमलों का निशाना बनता रहा है। गौरतलब है कि हमले से ठीक एक दिन पहले, शुक्रवार को दूतावास ने इराक के लिए स्तर-चार (थ्रेट-4) की सुरक्षा चेतावनी जारी की थी। चेतावनी में स्पष्ट कहा गया था कि ईरान और उसके समर्थित मिलिशिया समूह अमेरिकी नागरिकों, हितों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना जारी रख सकते हैं।

ईरान की 'मौत का वारंट' तैयार! दुनिया देखेगी तीसरा विश्वयुद्ध? अमेरिका काटने जा रहा ईरान की जीवनरेखा?

तेहरान। ईरान युद्ध के दो हफ्तों बाद भी मध्य-पूर्व में तनाव का स्तर अपने चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर इस क्षेत्र के इतिहास की 'सबसे भीषण बमबारी' की है।

ईरान युद्ध के दो हफ्तों बाद भी मध्य-पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर इस क्षेत्र के इतिहास की 'सबसे भीषण बमबारी' की है। यह द्वीप न केवल एक प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र है, बल्कि इसे ईरान की 'आर्थिक जीवनरेखा' माना जाता है। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों को मिलाकर बने क्षेत्रफल से भी छोटा यह द्वीप ईरान के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ईरान के कुल तेल निर्यात का 90इ हिस्सा यहीं से संसाधित होता है। 2024 में ईरान ने तेल बिक्री से लगभग 78 अरब डॉलर कमाए, जिसका मुख्य केंद्र खर्ग ही था। यहाँ का समुद्र इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर यहाँ आसानी से डॉक कर सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप मुख्य भूमि ईरान (जो इराक से चार गुना बड़ा है) पर हमला करने के बजाय खर्ग द्वीप पर 'बूट्स ऑन द ग्राउंड' यानी जमीनी सेना उतारने का प्रलोभन महसूस कर सकते हैं। यह द्वीप मुख्य भूमि से लगभग 25-28 किलोमीटर दूर है। यदि अमेरिका इस पर अचानक कब्जा कर लेता है, तो ईरान के लिए कम समय में वहाँ सेना भेजना लगभग नामुमकिन होगा। खर्ग पर कब्जा करने का मतलब है ईरान की 90 प्रतिशत कमाई पर ताला लगा देना। इससे ट्रंप को ईरान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की अपार शक्ति मिल सकती है।

ईरान युद्ध के दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी अमेरिका और इज़राइल का एक मुख्य लक्ष्य – देश में सत्ता परिवर्तन – अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति यह भी जानते हैं कि मुख्य भूमि ईरान इराक या वेनेज़ुएला जैसा नहीं है और वहाँ जमीनी सेना उतारने से भारी जान-माल के नुकसान का जोखिम है, जो घरेलू राजनीति के लिहाज से भी खतरनाक रणनीति हो सकती है। दरअसल, ईरान इराक से चार गुना बड़ा है और वहाँ विशाल व ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका है।

हालाँकि खर्ग – जो लक्षद्वीप के सभी द्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी छोटा है और ईरान के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है – ऐसी जगह है जो किसी भी सैन्य कमांडर के लिए हमले के सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक मानी जा सकती है।

इस द्वीप के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। यह हमेशा गोपनीयता के आवरण में ढका रहता है और इसकी सुरक्षा आईआरजीसी के कमांडो करते हैं। ईरानियों के लिए इसे 'वर्जित द्वीप' कहा जाता है, जहाँ केवल चुनिंदा लोगों को ही जाने की अनुमति होती है। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? लगभग पाँच मील लंबा होने के बावजूद खर्ग असल में ईरान के तेल निर्यात का नियंत्रण केंद्र है।

खर्ग द्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

दिलचस्प बात यह है कि 1979 की क्रांति के दौरान ईरान ने अमेरिका से खर्ग द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया था। आज यहाँ से ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा संसाधित होता है और यहाँ सालाना लगभग 950 मिलियन बैरल तेल का प्रबंधन किया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि खर्ग गहरे पानी के करीब स्थित है, जहाँ बड़े-बड़े तेल टैंकर सुरक्षित रूप से डॉक कर सकते हैं और कच्चा तेल लोड कर सकते हैं। यह तेल अधिकतर भारत और चीन जैसे एशियाई बाजारों में भेजा जाता है।

2024 में ईरान ने तेल की बिक्री से लगभग 78 अरब डॉलर यानी करीब 7.2 लाख करोड़ रुपये कमाए। इस कमाई का बड़ा हिस्सा खर्ग से बेचे गए कच्चे तेल से आया। यह पैसा न केवल सरकारी कामकाज के लिए जरूरी है, बल्कि ईरान के रक्षा प्रोजेक्ट्स – जैसे मिसाइल और ड्रोन बेड़े के विकास – के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।

इसलिए खर्ग पर कब्जा करना ईरानी शासन के लिए आर्थिक और सैन्य दोनों दृष्टियों से बड़ा झटका साबित हो सकता है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 Twitter: https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 Mobile No: 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/ इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)